



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 03 दिसम्बर, 2022 ई० (अग्रहायण 12, 1944 शक संवंत) [संख्या 49

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	943—958	3075	भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	981—996	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केंद्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोडपत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	255—256	975	भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	161—180	
			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के ऑकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के ऑकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	585—591	975
			स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड पत्र	..	1425

भाग १

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-१

प्रोन्नति

24 जनवरी, 2022, ई०

सं० 02-1001(002)/1/2022-1-I/135054/2022--श्रीमती सुजाता शर्मा, आई०ए०एस० (आन्ध्र प्रदेश 2006) को उनके मूल संवर्ग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपरटाईम वेतनमान रु० 1,44,200-2,18,200 (पे मैट्रिक्स में लेवल-14) में प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान किये जाने के दृष्टिगत नियुक्ति अनुभाग-५ की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या I/130954/2022, File No. 02-5/3/2021-5, दिनांक 10 जनवरी, 2022 के माध्यम से श्रीमती सुजाता शर्मा, आई०ए०एस० (आन्ध्र प्रदेश-2006) को उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपरटाईम वेतनमान रु० 1,44,200-2,18,200 (पे मैट्रिक्स में लेवल-14) में प्रोन्नति अनुमन्य की गयी है।

2—सुपरटाईम वेतनमान में प्रोन्नति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश शासन में तैनात श्रीमती सुजाता शर्मा को सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, प्रबन्ध निदेशक, पिकप, उत्तर प्रदेश तथा निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पदनाम एतद्वारा प्रदान किया जाता है।

आज्ञा से,
धनञ्जय शुक्ला,
विशेष सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस]

अनुभाग-१

पदोन्नति

04 अप्रैल, 2022 ई०

सं० 544/6-पु-1-22-1300(32)/88टीसी-I—उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा संवर्ग के निम्नलिखित रेडियो निरीक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक रेडियो अधिकारी (वेतन बैण्ड 15,600-39,100, ग्रेड पे रु० 5,400 लेवल-10) के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

चयन वर्ष 2020-2021, रिक्तियों की संख्या—०३

क्र० सं०	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	नाम	अभ्युक्ति
सर्वश्री / श्रीमती			
1	01	मुकेश कुमार दुबे	दिनांक 31.03.2021 को सेवानिवृत्त
2	02	सतेन्द्र सिंह	दिनांक 31.03.2021 को सेवानिवृत्त
3	04	वीरेन्द्र कुमार वर्मा	दिनांक 31.03.2021 को सेवानिवृत्त
4	05	भारत सिंह सेंगर	परिणामी रिक्ति के सापेक्ष

2—उक्त तालिका में क्रम सं०-१ पर उल्लिखित कार्मिक के प्रश्नगत चयन वर्ष में सेवा निवृत्त हो जाने के कारण घटित परिणामी रिक्ति के सापेक्ष ज्येष्ठता क्रमांक-५ पद उल्लिखित कार्मिक का चयन किया गया है।

3—प्रश्नगत चयन से सम्बन्धित यदि कोई याचिका विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को सहायक रेडियो अधिकारी के पद पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमत्य वेतन/भत्ते देय होंगे।

5—उक्त प्रोन्नत अधिकारियों की सेवा पर उ०प्र० शासन के प्रासंगिक नियम लागू होंगे।

आज्ञा से,
जय शंकर राय,
संयुक्त सचिव।

आबकारी विभाग

अनुभाग—1

प्रोन्नति

11 जुलाई, 2022 ई०

सं० 1741/ई-1/तेरह-2022-146/2016 टी०सी०-2—आबकारी विभाग के निम्नलिखित आबकारी निरीक्षकों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर वेतनमान 15,600-39100, ग्रेड पे-5,400 नया वेतनमान 56,100 से 1,77,500, लेबल-10 में वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही मौलिक रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र० सं०	नाम
1	श्री विनय कुमार निमेष
2	श्री रमेश चन्द्र
3	श्री रमेश राम
4	श्री सर्व सिंह चौहान
5	श्री देवेन्द्र सिंह रावत
6	श्री सूर्य प्रकाश

2—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3—उपर्युक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल आबकारी निरीक्षक के पद से कार्यमुक्त होकर सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की नियमित तैनाती के आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे। नियमित तैनाती होने तक वे पूर्ववत् कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,
निधि गुप्ता वत्स,
विशेष सचिव।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

अनुभाग-1

प्रोन्नति

18 फरवरी, 2022, ई०

सं० 219/22-1-2022-17/2003-I—कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में निम्नलिखित कारापालों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज से प्राप्त संस्तुति के आधार पर अधीक्षक

कारागार वेतनमान रु० 15,600-39100 ग्रेड पे रु० 5,400 (यथा संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु० 56,100-1,77,500) के पद पर अस्थायी रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

चयन वर्ष 2020-21

क्रमांक	नाम
1	श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी
2	श्री भोलानाथ मिश्र

चयन वर्ष 2021-22

क्रमांक	नाम
1	श्री रमाकान्त
2	श्री धर्मपाल सिंह
3	श्री शिव कुमार यादव
4	श्री राम शिरोमणि यादव

2—यदि कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन है, तो प्रश्नगत पदोन्नति उक्त रिट याचिका/प्रत्यावेदन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3—उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

चिकित्सा विभाग

अनुभाग-5

पदोन्नति

23 नवम्बर, 2021, ई०

सं० 1/2021/2214/पांच-5-2021—उत्तर प्रदेश दन्त सर्जन सेवा नियमावली, 1979 (यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश दन्त सर्जन सेवा संवर्ग के निम्नलिखित परामर्शदाताओं (वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 रु० 78,800-2,09,200) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निदेशक/ज्येष्ठ परामर्शदाता (वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 रु० 1,23,100-2,15,900) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	दन्त चिकित्साधिकारी का नाम
1	2	3
1	52	डा० सुनीता अम्बष्ट
2	5	डा० राजेश श्रीवास्तव
3	58	डा० राघवेन्द्र कुमार मिश्रा
4	60	डा० पुरुषोत्तम कुमार सिन्हा
5	61	डा० रमा कान्त श्रीवास्तव
6	91	डा० अमित माथुर
7	106	डा० शरद चन्द्र पाण्डेय
8	107	डा० शिप्रा पाण्डेय

1	2	3
9	111	डा० अवनीश कुमार गुप्ता
10	112	डा० अमित कुमार सिंह
11	115	डा० पुष्पा सिंह

2—उपर्युक्त प्रोन्नत दन्त चिकित्साधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं० 2/2021/2215/पांच-5-2021—उत्तर प्रदेश दन्त सर्जन सेवा नियमावली, 1979 (यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश दन्त सर्जन सेवा संवर्ग के निम्नलिखित ज्येष्ठ दन्त सर्जनों (वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 रु० 67,700-2,08,700) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से परामर्शदाता (वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 रु० 78,800-2,09,200) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	दन्त चिकित्साधिकारी का नाम
1	2	3
1	56	डा० नन्द किशोर
2	66	डा० जय प्रकाश वर्मा
3	70	डा० मणिकान्त गुप्ता
4	72	डा० जयेश करोली
5	74	डा० रत्ना गुप्ता
6	75	डा० दिनेश प्रताप सिंह
7	77	डा० भारती चतुर्वेदी
8	90	डा० प्रमोद कुमार
9	95	डा० सुचेता कुमारी गुप्ता
10	98	डा० गीता सिंह
11	105	डा० हेमलता सक्सेना
12	109	डा० पायल गुप्ता
13	113	डा० नवीन कुमार वर्मा
14	116	डा० आलोक राय
15	118	डा० संगीता सिंह
16	120	डा० प्रभुनाथ

2—उपर्युक्त प्रोन्नत दन्त चिकित्साधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
रविन्द्र,
सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन

अनुभाग-1

पदोन्नति

29 जून, 2022, ई०

सं० 562 / 18-1-2022-25(44) / 15—उ०प्र० उद्योग सेवा श्रेणी-1 के अधिकारी श्री आशुतोष त्रिपाठी, संयुक्त आयुक्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के फलस्वरूप अपर आयुक्त, उद्योग वेतनमान रु० 37,400-67,000 ग्रेड पे रु० 8,700 (पे मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

2—उपर्युक्त पदोन्नत अधिकारी को 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

3—उपर्युक्त अधिकारी की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

नवनीत सहगल,

अपर मुख्य सचिव।

सहकारिता विभाग

अनुभाग-2

स्थायीकरण

31 जनवरी, 2022, ई०

सं० 31 / 49-2-22-30(7) / 2007—उ०प्र० सहकारी सेवा नियमावली, 1979 के नियम-24 एवं उ०प्र० राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के नियम-4 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश के सीधी भर्ती संवर्ग के निम्नलिखित सहायक निबन्धकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ के पद पर एतद्वारा स्थायी किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रमांक	सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक का नाम	सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक पद पर योगदान की तिथि	स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4
1	श्री जहाँगीर खौ	20-06-2015	19-06-2017
2	श्री रवीन्द्र कुमार	14-07-2015	13-07-2017
3	श्री नवीन चन्द्र शुक्ला	06-11-2015	05-11-2017

आज्ञा से,

बी० चन्द्रकला,

विशेष सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

06 जुलाई, 2022, ई०

सं० 688 / 81-1-2022-09 / 2011—प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० के पत्रांक-ई०शा०-875 / 10-1-14(3) Vol-3, दिनांक 16 जून, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर

निम्नलिखित प्रान्तीय वन सेवा के अधिकारी (सहायक वन संरक्षक), वर्ष 2022 में अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर अपने नाम के सम्मुख अंकित तिथि से सेवानिवृत्त माने जायेंगे—

क्रमांक	सहायक वन संरक्षक का नाम	जन्म-तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4
1	श्री मेघराज	01-07-1962	30-06-2022

आज्ञा से,
गौरव वर्मा,
विशेष सचिव।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग

अनुभाग-4

सेवानिवृत्त

08 जुलाई, 2022, ई०

सं० 788 / 76-4-2022-2 / 4(21)2014ठी०सी०-लघु सिंचाई विभाग के श्रेणी-1 एवं 2 के निम्नलिखित अधिकारी स्तम्भ-4 में अंकित तिथि को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जायेंगे—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम व पदनाम	जन्म-तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	कार्यरत जनपद
1	2	3	4	5
सर्वश्री				
1	राजेश कुमार वर्मा अधिशासी अभियन्ता	01-08-1962	31-07-2022	भण्डार आपूर्ति खण्ड-लखनऊ।
2	नरेन्द्र बहादुर सिंह सहायक अभियन्ता	15-07-1962	31-07-2022	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई जनपद जौनपुर अतिरिक्त प्रभार अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, मिर्जापुर।
3	प्रमोद कुमार तिवारी सहायक अभियन्ता	15-07-1962	31-07-2022	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई जनपद अम्बेडकरनगर अतिरिक्त प्रभार अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, अयोध्या।
4	कुँवर पाल सिंह सहायक अभियन्ता	01-10-1962	30-09-2022	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई जनपद मुरादाबाद।
5	हरमिन्दर सूद अधिशासी अभियन्ता	15-12-1962	31-12-2022	परियोजना निदेशक, लघु सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन।
6	मनोज कुमार शाह अधिशासी अभियन्ता	10-12-1962	31-12-2022	लघु सिंचाई खण्ड, आजमगढ़।
7	राम कीरत सहायक अभियन्ता	01-03-1963	28-02-2023	प्रभार अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, वाराणसी।
8	संदीप कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्र सहायक अभियन्ता	15-05-1963	31-05-2023	प्रभार अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, जौनपुर।
9	शलभ श्रीवास्तव अधिशासी अभियन्ता	24-06-1963	30-06-2023	लघु सिंचाई खण्ड, अलीगढ़।

आज्ञा से,
डा० अम्बरीष कुमार सिंह,
उप सचिव।

ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग-2

पदोन्नति

10 मई, 2022 ई०

सं० एस-88 / 38-2-2022-2(12)एस / 2010टी०सी०-लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज के अनुमोदनोपरान्त निम्नांकित तालिका के क्रमांक 1 से 10 के समुख स्तम्भ-2 में अंकित ज्येष्ठ अनुदेशक को जिला प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर एवं क्रमांक 11 से 34 के समुख स्तम्भ-2 में अंकित ज्येष्ठ अनुदेशक को प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (विषयवार) के पद पर वेतनमान ₹० 15,600-39,100, वेतन बैण्ड-3, ग्रेड वेतन ₹० 5,400 (पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-10, ₹० 56,100-1,77,500) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप नवप्रोन्नत जिला प्रशिक्षण अधिकारियों एवं प्रसार प्रशिक्षण अधिकारियों को उनके नाम के समुख अंकित स्तम्भ-5 में अंकित संस्थान/जनपद में तात्कालिक प्रभाव से एतद्वारा तैनात किया जाता हैः—

क्र० सं०	नाम	पदोन्नति का पद	वर्तमान तैनाती	प्रोन्नति के उपरान्त तैनाती का संस्थान/जनपद
1	2	3	4	5
सर्वश्री / श्रीमती—				
1	अरविन्द लाल श्रीवास्तव	जिला प्रशिक्षण अधिकारी	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, दोरहीघाट, गोरखपुर	मऊ।
2	राकेश कुमार श्रीवास्तव	जिला प्रशिक्षण अधिकारी	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, कालाकांकर, प्रतापगढ़।	
3	विनय कुमार सिंह	जिला प्रशिक्षण अधिकारी	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बी०के०टी०	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, मथुरा।
4	हरिश्चन्द्र पटेल	जिला प्रशिक्षण अधिकारी	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, गोण्डा	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।
5	ज्ञानेन्द्र सिंह	जिला प्रशिक्षण अधिकारी	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, जौनपुर	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, गोरखपुर।
6	विपिन कुमार	जिला प्रशिक्षण अधिकारी	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बरेली	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, हमीरपुर।
7	रवि प्रकाश	जिला प्रशिक्षण अधिकारी	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान अफीम की कोठी, प्रतापगढ़।	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ।
8	शिव गणेश साहू	जिला प्रशिक्षण अधिकारी	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।
9	अजय प्रताप सिंह	जिला प्रशिक्षण अधिकारी	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान आसफपुर, बदायूँ	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, गाजियाबाद।
10	राजीव कुमार दुबे	जिला प्रशिक्षण अधिकारी	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, गोण्डा	राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।
11	डॉ नरेन्द्र पाल सिंह	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पंचायत)	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, मैनपुरी	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, लखावटी, बुलन्दशहर।

1	2	3	4	5
सर्वश्री / श्रीमती—				
12	निखिल कुमार	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि अभियंत्रण)	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, आगरा	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, चिरगांव, झाँसी।
13	शिव कुमार	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि अभियंत्रण)	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, अयोध्या	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, कालाकांकर, प्रतापगढ़।
14	प्रेम कुमार वर्मा	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि अभियंत्रण)	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, अयोध्या	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, अफीम की कोठी, प्रतापगढ़।
15	महाप्रताप चन्द्र	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि अभियंत्रण)	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, मथुरा	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बिचपुरी, आगरा।
16	अभिषेक मणि	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि अभियंत्रण)	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, देवरिया	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, गोण्डा।
17	पवन कुमार	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पशुपालन)	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बुलन्दशहर	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बड़ौत, बागपत।
18	सर्वेश कुमार	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पशुपालन)	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, पीलीभीत	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बदायूं।
19	कमलेश कुमार	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पशुपालन)	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, रामपुर	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, लखावटी, बुलन्दशहर।
20	कमल कुमार श्रीवास्तव	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पशुपालन)	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, वाराणसी	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, भोजीपुरा, बरेली।
21	सन्दीप कुमार	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पशुपालन)	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, हरदोई	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, मैनपुरी।
22	विमल कुमार सिंह	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पशुपालन)	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, वाराणसी	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, गाजीपुर।
23	अमित नारंग	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पशुपालन)	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, विजनौर	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, सहारनपुर।
24	विजय सिंह	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (पशुपालन)	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, इटावा	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, मैनपुरी।

1	2	3	4	5
सर्वश्री / श्रीमती—				
25	आरती सिंह	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी(महिला कल्याण)	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, इटावा	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बिचपुरी, आगरा।
26	सुधा तिवारी	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी(महिला कल्याण)	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, गाजियाबाद	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, मनिहारन, सहारनपुर।
27	डॉ मनोज कुमार	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी(पौध संरक्षण)	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, झाँसी	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बकेवर, इटावा।
28	संदीप कुमार पुनिया	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी(पौध संरक्षण)	जिल्हा ग्राम्य विकास संस्थान, दादरी, गौतमबुद्धनगर	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, बकेवर, इटावा।
29	राधारमण प्रसाद	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी(पौध संरक्षण)	जिल्हा ग्राम्य विकास संस्थान, सुल्तानपुर	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, चिरगाँव, झाँसी।
30	मनोज कुमार	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (जनस्वारश्य)	जिल्हा ग्राम्य विकास संस्थान, बाराबंकी	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, गाजियाबाद।
31	पुष्पेन्द्र कुमार	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि प्रसार),	शोध अधिकारी, राज्य क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, दोहरीघाट, नियोजन विभाग में कार्यरत (03 वर्ष के लिये)	मऊ।
32	अरुण कुमार पाण्डेय	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (शस्य विज्ञान),	जिल्हा ग्राम्य विकास संस्थान, सीतापुर	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, रायबरेली।
33	पंकज कुमार	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (शस्य विज्ञान),	जिल्हा ग्राम्य विकास संस्थान, बरेली	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, आसफपुर, बदायूं।
34	संजय कुमार	प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (मृदा विज्ञान),	जिल्हा ग्राम्य विकास संस्थान, सीतापुर	राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।

3—उपर्युक्त नव-प्रोन्नत अधिकारियों की परिवेक्षा अवधि 02 वर्ष की होगी।

4—नवप्रोन्नत अधिकारी अपने नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर तत्संबंधी कार्यभार प्रमाणक शासन एवं महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाबा, लखनऊ को उपलब्ध करा दें। संबंधित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

अनुभाग-1
13 जून, 2022 ई०

सं० R124 / 38-1-2022-01 पदोन्नति / 2021-उप्र० प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे, मैट्रिक्स लेवल 11 (रु० 67,700-2,08,700) में कार्यरत श्रीमती कमलेश सचान, उपायुक्त (स्वतः रोजगार), अमरोहा को उनसे कनिष्ठ

श्री ओम प्रकाश आर्य की प्रोन्नति तिथि 09 मई, 2022 से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे मैट्रिक्स लेवल-12(रु० 78,800-2,09,200) के पद पर नोशनल (प्राक्कल्पिक) रूप से नियमित पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2—उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्रीमती कमलेश सचान अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करती रहेंगी।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

युवा कल्याण विभाग

तैनाती

06 जून, 2022 ई०

सं० 1080/पचास-यु०क०-2022-52(विविध)/2013टी०सी०—युवा कल्याण अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियुक्ति आदेश संख्या-761/पचास-यु०क०-2022-52(विविध)/2013 दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के द्वारा श्री वैश्विक डबास, पुत्र श्री सुरेश कुमार डबास को जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी जनपद-मैनपुरी में तैनात किया गया था।

श्री वैश्विक डबास के निजी अनुरोध के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त श्री डबास को जनपद मैनपुरी के स्थान पर जनपद बुलन्दशहर में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
फलेन्द्र पाल सिंह राठौर,
उप सचिव।

मत्स्य उत्पादन विभाग

तैनाती

07 जून, 2022 ई०

सं० 19/2022/384/सत्रह-म-2022-5(1)/94टी०सी०—ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त तालिका के कालम संख्या-2 में अंकित निम्नलिखित अधिकारियों को लोक सेवा आयोग उ०प्र०, प्रयागराज के पत्र संख्या-29(II)/10/एस-2/पी/2021-22, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयन समिति की संस्तुति के आधार पर सहायक निदेशक मत्स्य, वेतन बैण्ड-3 रु०15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (पुनरीक्षित मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए, उन्हें तालिका में कालम संख्या-4 में अंकित पद व स्थान पर एतद्वारा तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति पदान करते हैं:-

क्र०स० अधिकारी का नाम/वर्तमान पद/तैनाती का स्थान	ज्येष्ठता क्रमांक	नवीन तैनाती का पद/स्थान	चयन वर्ष	
1	2	3	4	5
सर्वश्री / श्रीमती—				
1 राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक, कार्यालय प्रसाद, वाराणसी।	05	सहायक निदेशक मत्स्य, फर्रुखाबाद।	2020-21	
2 रवीन्द्र प्रसाद, ज्येष्ठ सत्स्य निरीक्षक, कार्यालय प्रसाद, वाराणसी।	06	सहायक निदेशक मत्स्य, गौतमबुद्ध नगर।	2021-22	
3 गिरीश चन्द्र, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक, कार्यालय प्रसाद, वाराणसी।	07	सहायक निदेशक मत्स्य, फतेहपुर।	2021-22	

1	2	3	4	5
	सर्वश्री / श्रीमती—			
4	राजीव कुमार गुप्ता ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, चन्दौली।	08	सहायक निदेशक मत्स्य, मीर्जापुर।	2021-22
5	नीतू सिंह, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, बुलन्द शहर।	10	सहायक निदेशक मत्स्य, अमरोहा।	2021-22
6	शिवकुमार ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक, कार्यालय म०पा०वि०अभिकरण, मेरठ।	11	सहायक निदेशक मत्स्य, बुलन्द शहर।	2021-22

2—उक्त नव पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार-प्रमाणक शासन एवं निदेशक मत्स्य, उ०प्र०, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

3—उक्त पदोन्नत अधिकारियों को उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित) सेवानियमावली, 1993 यथा संशोधित 2001 तथा उ०प्र० सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 यथासंशोधित, 2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है।

4—उक्त पदोन्नत अधिकारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित) सेवानियमावली, 1993 यथा संशोधित एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों से आच्छादित होंगे।

आज्ञा से,
राम सहाय यादव,
विशेष सचिव।

आयुष विभाग

अनुभाग-1
नियुक्ति
04 जनवरी, 2022 ई०

सं० 01/96-आयुष-1-2022-227/2020—राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2020 (यथा संशोधित 2021) की धारा-4(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत डा० अवधेश कुमार सिंह, निदेशक एवं प्रधानाचार्य, शुभदीप आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, इन्दौर मध्य प्रदेश को महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के प्रथम कुलपति के रूप में वेतनमान रूपये 2,10,000 (मूल वेतन+अन्य भत्ते) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या अरसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव।

07 जनवरी, 2022 ई०

सं० 4533/96-आयुष-1-2021-231/2015टी०सी०—लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज के पत्र संख्या-76/02/डी०आर०/एस-11/2016-17 टी०सी०-4, दिनांक 29 जुलाई, 2021 द्वारा प्रदेश के राजकीय यूनानी महाविद्यालय में प्रवक्ता इल्मुल सैदला के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन की संस्तुति के आधार पर डा० मो० अख्तर अली पुत्र श्री मो० अहसन जिया, ग्राम लिकायत अली रोड, लाईन, मुहल्ला थाना सदर, जनपद चतरा, झारखण्ड

को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक यूनानी के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में प्रवक्ता इल्मुल सैदला के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधिक लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गापनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

[8] समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त की दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें को आपत्ति नहीं होगी।

(8) सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अस्थर्थन निरस्त करने पर शासन सतर पर विचार किया जायेगा।

(9) उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त यूनानी चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ०प्र० द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

04 मई, 2022 ई०

सं० 1546I / 96-आयुष-1-2022-डब्लू-38 / 2022-डा० रखिण्डा बेग पत्नी सैयद तनवीर अहमद, निवासिनी-143 डी, सेक्टर एम आशियाना कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ को राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय,

लखनऊ में रीडर जराहत के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने सम्बन्धी आयुष अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1301/96-आयुष-1-2022-डब्लू-38/2022, दिनांक 04 मई, 2022 के बिन्दु-(9) के नीचे बिन्दु-(10) की शर्त निम्नवत् है—

(10) “डा० रण्जन्दा बेग पत्नी सैयद तनवीर अहमद की रीडर पद पर उक्त नियुक्ति, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-ए-835/2022 डा० अलबीना बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।”

आयुष अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1301/96-आयुष-1-2022-डब्लू-38/2022, दिनांक 04 मई, 2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त कार्यालय-ज्ञाप की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

24 जून, 2022, ई०

सं० 2165II/96-आयुष-1-2022-231/2015टी०सी०-लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज के पत्र संख्या-80/02/डी०आर०/एस-11/2018-19, दिनांक 10 अगस्त, 2021 द्वारा प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता इल्मुल अदविया के 01 अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की संस्तुति के आधार पर डा० शेख अजीज अहमद मकबूल पुत्र श्री मकबूल अहमद, निवासी ग्राम रमवापुर नायक, पोस्ट ईंटियाथोक, जिला गोण्डा को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक यूनानी के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में प्रवक्ता इल्मुल अदविया के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियाँ।

- [4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
- [5] गापनीयता का प्रमाण-पत्र।
- [6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
- [7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र

[8] समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त की दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें को आपत्ति नहीं होगी।

(8) सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(9) उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त यूनानी चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ०प्र० द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं० 2165III / 96-आयुष-1-2022-231 / 2015टी०सी०-लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज के पत्र संख्या-232 / 12 / डी०आर० / एस-11 / 2014-15 टी०सी०-2, दिनांक 25 जनवरी, 2022 द्वारा प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता तशरीह उल बदन के 01 अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की संस्तुति के आधार पर डा० फरजाना खातून सुपुत्री श्री जमील अहमद निवासी गांवगोड़िया, मकबूल नगर, पोस्ट आफिस गांधी नगर, बस्ती को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक यूनानी के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में प्रवक्ता तशरीह उल बदन के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

(1) सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर ररखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय जारी पर शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तो इत्यादि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379 / दस-2005-31(9) / 2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियाँ।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गापनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

[8] समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त की दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें को आपत्ति नहीं होगी।

(8) सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन सतर पर विचार किया जायेगा।

(9) उत्तर प्रदेश राज्य अयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यपकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त यूनानी चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ०प्र० द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
सुखलाल भारती,
विशेष सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 03 दिसम्बर, 2022 ई० (अग्रहायण 12, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

4 नवम्बर, 2022 ई०

सं० 7326(i) / आठ-वि०भू०अ०अ०-सि०नगर / अधि०स०० / 2022-23-उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच-खलीलाबाद बी० जी० रेल लाईन के नर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील-बौसी, परगना-बौसी पूरब, ग्राम-खेसरही में स्थित 2.4374893 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 6084 / आठ-वि०भू०अ०अ० सि० नगर / अधि०स०० / 2020-21 / दिनांक 27 जून, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट उ०प्र० में दिनांक 20 अगस्त, 2022 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेन्ट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को पिरयोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्यापित प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19 सितम्बर, 2022 पर विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची 'क' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख' में उल्लिखित जिला-सिद्धार्थनगर, तहसील-बौसी, परगना-बौसी पूरब, ग्राम-खेसरही की शून्य है। भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

अनुसूची-क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
हेक्टेयर						
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	खेसरही	129	0.1285978
2					130	0.1207098
3					142	0.0472425
4					138	0.0194221
5					124	0.0410057
6					144	0.2140371
7					145	0.1619808
8					217	0.1709041
9					237	0.1700385
10					238	0.0190
11					231	0.0200
12					230	0.0583227
13					212	0.0126841
14					240	0.1255053
15					241	0.1496538
16					245	0.6802376
17					265	0.1608703
कुल क्षेत्रफल						2.3002122

अनुसूची-ख
(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
हेक्टेयर						
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	खेसरही	शून्य	शून्य

नोट:-—समुचित सरकार द्वारा चयनित सामाजिक समाधात/प्रबन्धन अध्ययन कर्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित अर्जन से भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है तथा अध्ययन कर्ता संस्था की आख्या पर बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी०जी० रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाधात/प्रबन्धन रिपोर्ट से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है। सम्बन्धित तहसील की आख्या के अनुसार भी कोई कुटुम्ब विस्थापित नहीं हो रहा है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

November 4, 2022

[Under sub-section (1) of section 19 of the act]

No. 7326(I)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthanagar/Notification/2022-23—Whereas preliminary notification no. 6084/VIII-S.L.A.O.-SDR/Notification/2021 dated June 27, 2022 was issued under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 2.4374893 hectares of land in Village-Khesrahi, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose, namely, project Bahraich-Khalilabad B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur and lastly published on 20th of August, 2022 in Government Gazette U.P. The Deputy Collector/Assistant Collector was not appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families, because no families are likely to be displaced due to land acquisition.

After considering the report of the Collector for the purpose of land acquisition submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of zero hect. in Village-Khesrahi, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District-Siddharthnagar as given in Schedule "B" has been identified as the rehabilitation and resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families.

SCHEDULE-A
(Land under proposed acquisition)

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6	7
<i>Hectares</i>						
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Khesrahi	129	0.1285978
2					130	0.1207098
3					142	0.0472425
4					138	0.0194221
5					124	0.0410057
6					144	0.2140371
7	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Khesrahi	145	0.1619808
8					217	0.1709041
9					237	0.1700385
10					238	0.0190
11					231	0.0200

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
12				230		0.0583227
13				212		0.0126841
14				240		0.1255053
15				241		0.1496538
16				245		0.6802376
17				265		0.1608703
Total ..						2.3002122

SCHEDEULE-B
(Land identified as settlement area for displaced families)

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Khesrahi	Zero	Zero

NOTE : Social Impact Assessment study conducted by agency has been declared that No families are likely to be displaced due to land acquisition. However multi-disciplinary expert group unanimously recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad New Rail Line Project. Concern tehsil has been also submitted report that no families are likely to be displaced due to land acquisition.

A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

सं० 7327(i) / आठ-वि०भ०अ०अ०-सि०नगर / अधि०स०० / 2022-23-उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन / जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच-खलीलाबाद बी० जी० रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-सवाडाड में स्थित 2.9508209 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 6085 / आठ-वि०भ०अ०अ० सि० नगर / अधि०स०० / 2020-21 / दिनांक 27 जून, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट उप्र० में दिनांक 20 अगस्त, 2022 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर / असिस्टेन्ट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को

परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया हैं क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19 सितम्बर, 2022 पर विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख' में उल्लिखित जिला-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-सवाडाड़ की शून्य हेठो भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
हेक्टेयर						
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	सवाडाड़	157	0.0241724
2					159	0.0503846
3					163	0.0983116
4					165	0.0383726
5					166	0.0439996
6					167	0.053965
7					168	0.052564
8					169	0.1836679
9					170	0.2229946
10					171	0.2167113
11					172	0.4384514
12					173	0.2791024
13					174	0.1783354
14					175	0.1832994
15					176	0.2193255
16					177	0.1857909
17					178	0.4647573
18					189	0.016615
कुल क्षेत्रफल						2.9508209

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
हेक्टेयर						
2	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	सवाडाड	शून्य	शून्य

नोट:—समुचित सरकार द्वारा चयनित सामाजिक समाघात/प्रबन्धन अध्ययन कर्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित अर्जन से भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है तथा अध्ययन कर्ता संस्था की आख्या पर बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी०जी० रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात/प्रबन्धन रिपोर्ट से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है। सम्बन्धित तहसील की आख्या के अनुसार भी कोई कुटुम्ब विस्थापित नहीं हो रहा है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

November 4, 2022

No. 7327(I)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthanagar/Notification/2022-23—Whereas preliminary notification no. 6085/VIII-S.L.A.O.-SDR/Notification/2021 dated June 27, 2022 was issued under sub-section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 2.9508209 hectares of land in Village-Swaadad, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose, namely, project Bahraich-Khalilabad B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur and lastly published on 20th of August, 2022 in Government Gazette U.P. The Deputy Collector/Assistant Collector was not appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families, because no families are likely to be displaced due to land acquisition.

After considering the report of the Collector for the purpose of land acquisition submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of zero hect. in Village-Swaadad, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District-Siddharthnagar as given in Schedule "B" has been identified as the rehabilitation and resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families.

SCHEME-A
(Land under proposed acquisition)

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6	7
Hectares						
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Swaadad	157	0.0241724

1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
2	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Swaadad	159	0.0503846
3					163	0.0983116
4					165	0.0383726
5					166	0.0439996
6					167	0.053965
7					168	0.052564
8					169	0.1836679
9					170	0.2229946
10					171	0.2167113
11					172	0.4384514
12					173	0.2791024
13					174	0.1783354
14					175	0.1832994
15					176	0.2193255
16					177	0.1857909
17					178	0.4647573
18					189	0.016615
Total ..					2.9508209	

SCHEDULE-B
(Land identified as settlement area for displaced families)

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Swaadad	Zero	Zero

NOTE : Social Impact Assessment study conducted by agency has been declared that No families are likely to be displaced due to land acquisition. However multi-disciplinary expert group unanimously recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad New Rail Line Project. Concern tehsil has been also submitted report that no families are likely to be displaced due to land acquisition.

A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

सं० 7328(i) / आठ-वि०भू०अ०अ०-सि०नगर / अधी०स०० / 2022-23-उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन / जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच-खलीलाबाद वी० जी० रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील-बांसी, परगना-बांसी पूरब, ग्राम-पिढ़िया में स्थित 1.9523544 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 6093 / आठ-वि०भू०अ०अ० सि० नगर / अधी०स०० / 2020-21 / दिनांक 27 जून, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट उ०प्र० में दिनांक 27 अगस्त, 2022 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर / असिस्टेन्ट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्यापित प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19 सितम्बर, 2022 पर विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख' में उल्लिखित जिला-सिद्धार्थनगर, तहसील-बांसी, परगना-बांसी पूरब, ग्राम-पिढ़िया की शून्य है० भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

अनुसूची-क (प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
हेक्टेयर						
1	सिद्धार्थनगर	बांसी	बांसी पूरब	पिढ़िया	114	0.6887458
2					115	0.185118
3					130	0.6475025
4					126	0.0019915
5					127	0.3140
6					128	0.1089342
कुल						1.946292
क्षेत्रफल						

अनुसूची-ख (विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
हेक्टेयर						
1	सिद्धार्थनगर	बांसी	बांसी पूरब	पिढ़िया	शून्य	शून्य

नोट:-समुचित सरकार द्वारा चयनित सामाजिक समाधात/प्रबन्धन अध्ययन कर्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित अर्जन से भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है तथा अध्ययन कर्ता संस्था

की आख्या पर बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच—खलीलाबाद बी०जी० रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाधात / प्रबन्धन रिपोर्ट से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है। सम्बन्धित तहसील की आख्या के अनुसार भी कोई कुटुम्ब विस्थापित नहीं हो रहा है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

NOTIFICATION

November 4, 2022

No. 7328(I)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthanagar/Notification/2022-23—Whereas Preliminary notification no. 6093/VIII-S.L.A.O.-SDR/Notification/2021 dated June 27, 2022 was issued under sub-section (1) of section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 1.946292 hectares of land in Village-Pidhiya, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose, namely, project Bahraich-Khalilabad B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur and lastly published on 27th of August, 2022 in Government Gazette U.P. The Deputy Collector/Assistant Collector was not appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families, because no families are likely to be displaced due to land acquisition.

After considering the report of the Collector for the purpose of land acquisition submitted in pursuance to provision under sub Section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of zero hect. in Village-Pidhiya, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District-Siddharthnagar as given in Schedule "B" has been identified as the rehabilitation and resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families.

SCHEDULE-A (Land under proposed acquisition)

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6	7
<i>Hectares</i>						
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pidhiya	114	0.6887458
2					115	0.185118
3					130	0.6475025
4					126	0.0019915
5					127	0.03140
6					128	0.1089342
Total ..						1.946292

SCHEDULE-B**(Land identified as settlement area for displaced families)**

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6	7
<i>Hectares</i>						
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pidhiya	Zero	Zero

NOTE : Social Impact Assessment study conducted by agency has been declared that No families are likely to be displaced due to land acquisition. However multi-disciplinary expert group unanimously recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad New Rail Line Project. Concern tehsil has been also submitted report that no families are likely to be displaced due to land acquisition.

A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

सं० 7329(i) / आठ-वि०भ०आ०आ०-सि०नगर / अधि०सू० / 2022-23-उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन / जनरल, नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच-खलीलाबाद बी० जी० रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-सिंहोरवा में स्थित 2.5946856 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 6081 / आठ-वि०भ०आ०आ० सि० नगर / अधि०सू० / 2020-21 / दिनांक 27 जून, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट उ०प्र० में दिनांक 20 अगस्त, 2022 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर / असिस्टेन्ट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया हैं क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा हैं।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्यापि प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19 सितम्बर, 2022 पर विचारोपान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची 'क' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची 'ख' में उल्लिखित जिला-सिद्धार्थनगर, तहसील-बॉसी, परगना-बॉसी पूरब, ग्राम-सिंहोरवा की शून्य हेठो भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

अनुसूची-क**(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)**

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
हेक्टेयर						
1	सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	सिंहोरवा	1	0.0910374
2					12	0.1043853

1

2

3

4

5

6

7

હેક્ટેયર

3

13

0.2380

4

14

0.1025341

5

8

0.2508367

6

33

0.0311876

7

29

0.1039845

8

32

0.0470

9

30

0.0456084

10

41

0.034089

11

42

0.2312417

12

53

0.0166789

13

54

0.0167347

14

55

0.001684

15

44

0.0446543

16

45

0.0327404

17

46

0.2306809

18

57

0.1181464

19

58

0.0768844

20

60

0.0811857

21

61

0.0249368

22

97

0.0321617

23

63

0.0384612

24

64

0.1445501

25

65

0.203256

26

66

0.1018556

27

67

0.0580303

કુલ ક્ષેત્રફળ

2.5025461

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
हेक्टेयर						
1	सिद्धार्थनगर	बांसी	बांसी पूरब	सिंहोरवा	शून्य	शून्य

नोट:—समुचित सरकार द्वारा चयनित सामाजिक समाघात/प्रबन्धन अध्ययन कर्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित अर्जन से भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है तथा अध्ययन कर्ता संस्था की आख्या पर बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्व सम्मति से बहराइच-खलीलाबाद बी०जी० रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात/प्रबन्धन रिपोर्ट से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है। सम्बन्धित तहसील की आख्या के अनुसार भी कोई कुटुम्ब विस्थापित नहीं हो रहा है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

No. 7329(I)/VIII/S.L.A.O.-Siddharthanagar/Notification/2022-23—Whereas Preliminary notification no. 6081/VIII-S.L.A.O.-SDR/Notification/2021 dated June 27, 2022 was issued under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 2.5946856 hectare of land in Village-Singhorva, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District-Siddharthanagar is required for public purpose, namely, project Bahraich-Khalilabad B. G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur and lastly published on 20th of August, 2022 in Government Gazette U.P. The Deputy Collector/Assistant Collector was not appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families, because no families are likely to be displaced due to land acquisition.

After considering the report of the Collector for the purpose of land acquisition submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of zero hect. in Village-Singhorva, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District-Siddharthanagar as given in Schedule "B" has been identified as the rehabilitation and resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families.

SCHEDE-A
(Land under proposed acquisition)

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6	7
<i>Hectares</i>						
1	Siddharthanagar	Baansi	Baansi Purab	Singhorva	1	0.0910374
2					12	0.1043853

1	2	3	4	5	6	7
<i>Hectares</i>						
3	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Singhorva	13	0.2380
4					14	0.1025341
5					8	0.2508367
6					33	0.0311876
7					29	0.1039845
8					32	0.0470
9					30	0.0456084
10					41	0.034089
11					42	0.2312417
12					53	0.0166789
13					54	0.0167347
14					55	0.001684
15					44	0.0446543
16					45	0.0327404
17					46	0.2306809
18					57	0.1181464
19					58	0.0768844
20					60	0.0811857
21					61	0.0249368
22					97	0.0321617
23					63	0.0384612
24					64	0.1445501
25					65	0.203256
26					66	0.1018556
27					67	0.0580303
Total ..					2.5025461	

SCHEDULE-B**(Land identified as settlement area for displaced families)**

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6	7
<i>Hectares</i>						
1	Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Singhorva	Zero	Zero

NOTE : Social Impact Assessment study conducted by agency has been declared that No families are likely to be displaced due to land acquisition. However multi-disciplinary expert group unanimously recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad New Rail Line Project. Concern tehsil has been also submitted report that no families are likely to be displaced due to land acquisition.

A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

22 नवम्बर, 2022 ई०

प्रारूप—19

(नियम—27 का उपनियम (1))

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

सं० 770/आठ-वि०भ०आ०आ० (सं०सं०)/वाराणसी-हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी, एल०पी०जी० क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जनपद वाराणसी में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के एल०पी०जी० भराई संयंत्र निर्माण हेतु ग्राम इसरवार, परगना कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी में 2.3780 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना सं०-३७२/ दिनांक 25 अगस्त, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट में प्रकाशन दिनांक 3 सितम्बर, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेन्ट कलेक्टर, वाराणसी को परियोजना में प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थान के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा उल्लिखित जिला वाराणसी,

तहसील राजातालाब, परगना कसवार राजा, ग्राम इसरवार की उक्त अनुसूची में वर्णित 2.3780 हेक्टर भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

मा० राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा-(2) के अधीन घोषणा के प्रकाशन हेतु समुचित सरकार जिला कलेक्टर, वाराणसी को निर्देशित करते हैं—

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
हेक्टेयर					
वाराणसी	राजातालाब	कसवार राजा	इसरवार	180	1.35
				181	1.028
				योग...	2.378

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल-नक्शा कलेक्टर, वाराणसी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी, वाराणसी।

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

Declaration by the appropriate government/collector

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]

NOTIFICATION

November 22, 2022

No. 770/VIII-S.L.A.O.(J.O.)—Varanasi—Whereas preliminary notification no. 372 dated August 25, 2022 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 2.3780 hectares of land in Village-Isarwar, Pargana-Kaswar Raja, Tehsil-Rajatalab, District-Varanasi, is required for public purpose, namely, Project-Hindustan Petroleum Corporation Limited Varanasi through LPG Regional Office and lastly published on dated September 3, 2022. The Deputy Collector/Assistant Collector Varanasi was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and no

family is being displaced as a result of acquisition of 2.3780 hectares of land mentioned in the above schedule of District-Varanasi, Tehsil-Rajatalab, Pargana-Kaswar Raja, Village-Isarwar.

The Governor further directs that the appropriate Government direct the District Collector, Varanasi for publication of the declaration under sub-section (2) of section 19 of the Act.

SCHEDULE-A
(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
<i>Hectares</i>					
Varanasi	Rajatalab	Kaswar Raja	Isarwar	180	1.35
				181	1.028
				Total...	2.378

NOTE—A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector, Varanasi.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 03 दिसम्बर, 2022 ई० (अग्रहायण 12, 1944 शक संवत्)

भाग ३

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख—नगर पंचायत,
खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

खण्ड-घ—जिला पंचायत कार्यालय आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर

17 नवम्बर, 2022 ई०

सं० 1992 /स्थानिक०स०-उपविधि / 22-23—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 की उप धारा-2 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जनपद सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू मोरम रेत या अन्य खनिजों गिट्टी, पत्थर, बोल्डर, सुरखी, चूना, भर्सी, कोयला, बजरी खारों से निकलने वाली मिट्टी लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशुचालित वाहन यथा ट्रेक्टर ट्राली, ट्रक, मिनी ट्रक, डम्पर, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ऊँटगाड़ी, घोड़गाड़ी या मानव चालित नौका से उपर्युक्त खनिज परिवहन करने वाले निम्नलिखित ढोने वाले वाहनों से शुल्क लगाने हेतु नियंत्रित एवं नियमित करने के लिए उपविधि बनायी गयी है, जो विज्ञप्ति संख्या-4329 /स्थानिक०स०-उपविधि-2018-19, दिनांक 28 फरवरी, 2019 से लागू है, में विर्णिष्ट मदों की दरों में संशोधन /वृद्धि तथा कठिपय अन्य मद जो उपर्युक्त उपविधि में सम्मिलित नहीं थे, को सम्मिलित किये जाने हेतु संशोधन प्रस्तावित है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित किया जाता है। यह संशोधित उपविधि गजट में प्रकाशन होने की तिथि से लागू समझी जाये। इस उपविधि के लागू होने के उपरान्त पूर्व प्रख्यापित उपविधि जो दिनांक 08 फरवरी, 2019 से लागू है, का संशोधित अंश निरस्त समझा जाये।

रेट लिस्ट

क्रमांक	विवरण	लागू दर	संशोधित दर
1	2	3	4
1	पशुओं द्वारा खीचें जाने वाली गाड़ी	15.00 प्रतिफेरी	18.00 प्रतिफेरी
2	मानव चालित नाव	25.00 प्रतिफेरी	29.00 प्रतिफेरी

1	2	3	4
3	ट्रैक्टर ट्राली	60.00 प्रतिफेरी	70.00 प्रतिफेरी
4	मिनी ट्रक (लाइट गुड्स विहिकल्स)	115.00 प्रतिफेरी	133.00 प्रतिफेरी
5	ट्रक (लाइट गुड्स विहिकल्स 06 चक्का)	175.00 प्रतिफेरी	202.00 प्रतिफेरी
6	भारी ट्रक (हैवी गुड्स विहिकल्स 10 चक्का या अधिक)	230.00 प्रतिफेरी	265.00 प्रतिफेरी
7	भारी ट्रक (हैवी गुड्स विहिकल्स 14 चक्का या अधिक)	300.00 प्रतिफेरी	345.00 प्रतिफेरी
8	भारी ट्रक (हैवी गुड्स विहिकल्स 18 चक्का या अधिक)	400.00 प्रतिफेरी	460.00 प्रतिफेरी

ह० (अस्पष्ट),
आयुक्त,
विन्ध्याचल मण्डल,
मीरजापुर।



सरकारी गज़्ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 03 दिसम्बर, 2022 ई० (अग्रहायण 12, 1944 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 20 अक्टूबर, 2022 ई०
28 आश्विन, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं० 82/उ०प्र०-वि०स०/10/2017 (इला०)–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2017 की निर्वाचन अर्जी संख्या 10 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 12 सितम्बर, 2022 के निर्णय को एतद्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,
अमित कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 20th October, 2022
28th Asvina, 1944 (Saka).

NOTIFICATION

No. 82/UP-LA/10/2017 (Alld.)—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 12th September, 2022 of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in Election Petition No. 10 of 2017.

By order,
AMIT KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Election Petition No. 10 of 2017

(Under Section 80/81 of Representation of the People Act, 1951)

District : Allahabad.

Anugrah Narayan Singh, son of Late S.B. Singh,
 Resident of 439, New Mumfordganj, Allahabad,
 District – Allahabad.

*... Petitioner****Versus***

Harsh Vardhan Bajpayee, son of Sri. Ashok Kumar, Bajpayee,
 Resident of 109, Rambagh, Allahabad,
 District – Allahabad.

*... Respondent***Reserved on 29.07.2022****Delivered on 12.09.2022****Court No. - 73****Case :- ELECTION PETITION No. - 10 of 2017****Petitioner :-** Anugrah Narayan Singh**Respondent :-** Harsh Vardhan Bajpayee**Counsel for Petitioner :-** In Person, Anugrah Narayan Singh (In Person), Ravindra Singh, Shiv Sagar Singh**Counsel for Respondent :-** Manish Goyal, Amit Sharma, K. R. Singh, Mithilesh Kumar Rai, Prabath Kumar Bajpai, Ravi Shankar Prasad***Hon'ble Raj Beer Singh, J.*****Order on Application Nos. 19 of 2022 and 20 of 2022 filed in Election Petition No. 10 of 2017 (Anugrah Narayan Singh v. Harsh Vardhan Bajpayee)**

1. The Civil Misc. Application No. 19 of 2022 has been filed by the respondent with prayer to dismiss the election petition as infructuous, whereas, the Civil Misc. Application No. 20 of 2022 has been filed by the Petitioner raising objections against that application.

2. The facts in brief of the matter are that in the month of February, 2017 general elections were held to elect the Members of the State Legislative Assembly, U.P. The petitioner as well as the respondent contested election from the 262 Allahabad City North Constituency. The last date of nomination for this constituency was 06.02.2017. After election, as per declaration of Returning Officer, the respondent has received 89191 votes whereas the petitioner has received 54166 votes and thus, the respondent was declared elected. The petitioner filed this election petition under section 80/81 of the Representation of the People Act (hereinafter after refereed as 'R.P. Act') challenging the election of the respondent/returned candidate and seeking following relief :

(A) Declare the election of respondent as Member of Legislative Assembly from 262 Allahabad City North Assembly Constituency, District Allahabad, as null and void and set aside the same.

(B) Pass such other order or direction which the Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts of the case.

(C) Award costs to the petitioner.

3. During pendency of the election petition, the Legislative Assembly came to be dissolved in the month of February/ March, 2022 after the term of five years was over. In view of the above-stated fatal background, the respondent has filed the above-stated Civil Misc. Application No. 19 of 2022 with prayer that the election petition may be dismissed as infructuous.

4. Heard Sri Sailendra Kumar, learned Senior Advocate assisted by Sri Shiv Sagar Singh, learned counsel for the petitioner, Sri Ravi Shankar Prasad, learned Senior Advocate assisted by Sri Mithilesh Kumar, learned counsel for the respondent, Sri Manish Goel, learned Senior Advocate/AAG and perused the record.

5. Learned senior counsel for the petitioner argued that though the term of assembly is over and the Assembly has already been dissolved but as the election of the respondent was being challenged inter-alia on the ground of corrupt practice and thus, the instant election petition is still maintainable, as in case this election petition succeeds, it entails several disqualification including a bar on the respondent to contest the election for a period of six years and thus, the election petition can not be dismissed as infructuous. It was submitted that the respondent has committed corrupt practice under Section 123(2) of the R.P. Act by interfering in free exercise of electoral rights of the electors by not disclosing his liabilities and his correct educational qualification in his affidavit of nomination paper. Further, the respondent committed the corrupt practice under Section 123(4) of the R.P. Act by publishing a false statement of fact, which he believed to be false, and did not believe to be true, regarding his own personal character and conduct. It was submitted that the election of the respondent is liable to be declared void, due to improper acceptance of his nomination paper and also due to commission of corrupt practice by him.

6. Elaborating his arguments, it was submitted by learned Senior counsel for the petitioner that the respondent has also contested election of Legislative Assembly from the same constituency in the year 2007, wherein he has shown his educational qualification as B.Tech. from University of Shefield, England passed in the year 2003 and the highest degree was shown "Master of Finance and Control" from Delhi University in the year 2006. The respondent again contested election from the said constituency in the year 2012, wherein, same qualification and degrees were shown but while filing his nomination for election from same constituency in the year 2017, he has shown his qualification and highest degree as B.Tech. from Seferred University, England, passed in the year 2007. It was submitted that as a matter of fact, there is no university by the name of "Seferred" in England. There is university of Shefield in England but it awards degree of B.E. in Chemical Engineering and not the degree of B.Tech. Further, in his nomination paper in the year 2007 and 2012 he has shown that he has degree of M.B.A. from Delhi University in the year 2006, whereas in the nomination paper of 2017, he has shown his B.Tech. degree passed in the year 2007 and thus if he has passed the degree of M.B.A. from University of Delhi in the year 2006, how he can pass B.Tech. examination from said University in U.K., in the year 2007, which is a two years course. In fact, the respondent has not cleared the M.B.A. degree from University of Delhi. Further, in the year 2007 and 2012 in his affidavit of nomination paper, he has claimed that he passed B.Tech. degree in the year 2003 from Shefield University, England but his name does not find place in Alumni of 2003 of the said University and all these facts go to show that the respondent did not obtain the alleged degree from University of Shefield, England and he has given false information in his affidavit/nomination paper.

7. Another ground pressed by learned senior counsel is that in his nomination paper, the respondent has shown his address as 109, Rambagh, Allahabad and this property was also mentioned by him in his nomination paper as one of the asset. There is an electricity connection in the said premises against which there were arrears of electricity dues of Rs. 3,00,050/- and that a recovery certificate was issued on 05.10.2016 and that amount was not paid till the filing of the nomination paper by the respondent but in respect of the same, the respondent has shown in his affidavit that there were no electricity dues against any of his asset. Further, the respondent has taken a housing loan from P.N.B., Civil Lines, Allahabad through account number 001200NC00801166 in respect of $\frac{1}{2}$ part of house no. 2, Minto Park House, Kydganj, Allahabad and said loan amount was shown by respondent in his affidavit of 2012 but in 2017 he has concealed the said loan amount, whereas said loan has not been paid/cleared till the date of filing of nomination paper, by the respondent. It was submitted that the respondent was under legal obligation to disclose the correct facts in his affidavit filed along with the nomination paper as it was for the information of electors to know the personal character and conduct of the candidate and thus, there was substantial defect in his nomination paper and accordingly his nomination paper was liable to be rejected.

8. It was further argued that during campaign in the election, the respondent got printed pamphlets and hand bills in which he mentioned his name as Er. Harsh Vardhan Bajpayee and he posed himself as a qualified Engineer and as referred above, he did not disclose his educational qualifications correctly and thus, it amounts to corrupt practice of undue influence.

9. It was next argued by learned senior counsel that a candidate is required to disclose facts about his educational qualification and government dues in the affidavit so that before casting their votes, the electors of the constituency would know about educational qualification as well as liabilities and personal character of candidate. The respondent has deliberately, in full knowledge of the facts, concealed and suppressed the truth and did not provide full and correct facts about his educational qualification and government dues and thereby he published incorrect and false statement of facts about his personal character and conduct which favourably prejudiced the prospects of his election and thus, he committed corrupt practice as defined under Section 123(4) of R. P. Act.

10. Referring to the provisions of Section 123 of R.P. Act and facts of the matter, learned senior counsel submitted that as there is a case to show that the respondent has committed corrupt practice within the meaning of section 123(2) and 123(4) of R. P. Act and thus this election petition must be proceeded further, as the respondent may entails several disqualifications including a bar for contesting an election for a period of six years. In support of his contentions, learned senior counsel has referred following case laws :-

- (a) *Shaligram Shrivastava v. Naresh Singh Patel*, SCC 2 (2003), 176
- (b) *People's Union For Civil Liberties (PUCL) and Anr. v. Union of India And Anr.*, SCC 4 (2003) 399
- (c) *Mairembam Prithviraj alias Prithviraj Singh v. Pukhrem Sharatchandra Singh*, SCC 2 (2017) 887
- (d) *Kisan Shankar Kathore v. Arun Dattatray Sawant And Ors.*, SCC 14 (2014) 162
- (e) *Resurgence India v. Election Commission of India And Anr.*, SCC 14 (2014) 189
- (f) *Madiraju Venkata Ramana Raju v. Peddireddigari Ramachandra Reddy And Ors.*, SCC 14 (2018) 1
- (g) *Sheodan Singh v. Mohan Lal Gautam*, AIR 1969 SC 1024
- (h) *Loknath Padhan v. Birendra Kumar Sahu*, AIR 1974 SC 505
- (i) *P.H. Pandian v. P Veldurai*, SCC 2013 (14) 685

(j) *Dhartipakar Madan Lal Agarwal v. Shri Rajiv Gandhi*, AIR 1987 SC 1577

(k) *Prem Pal Singh v. Satya Pal Singh Baghel And 10 Ors.*, [Election petition no. 12 of 2017, decided on 03.03.2020]

(l) *Bhikaji Keshao Joshi And Anr. v. Brijlal Nandlal Biyani And Ors.*, AIR 1955 SC 610

11. Sri Ravi Shankar Prasad, learned senior Advocate for the respondent as well as Sri Manish Goel, learned senior Advocate/ Additional Advocate General have argued that the petitioner is challenging the election of respondent to the State Legislative Assembly, Uttar Pradesh, wherein the respondent was elected as Member of State Assembly in the month of February / March 2017 and after its full term, that the said assembly has already been dissolved and thereafter fresh election to elect the members of State Assembly have already been held in the month of February/ March, 2022 and thus, the instant election petition has become infructuous, as the relief claimed by the petitioner cannot be granted. It was submitted that in the election petition, the petitioner has made averments regarding corrupt practice, allegedly committed by the respondent, but there is absolutely no material to substantiate the said averments and that no case of corrupt practice is made out. Learned senior counsel submitted that even if in the affidavit of respondent there was some incorrect information regarding educational qualifications of the respondent/returned candidate on the points like name of University or the year, in which he has passed the degree, it can hardly be fall within the purview of corrupt practices. Mere inaccuracy in the name of University like 'Seferred University', or inconsistency regarding the year, in which he has passed the said B.Tech degree cannot be considered as a material concealment or false information. The claim of petitioner that the respondent/returned candidate did not pass the degree of B.Tech. is not supported by any credible material. Merely because in list of alumni of the year 2003 of Shefield University (U.K.) the name of respondent/returned candidate does not find place, it can hardly be sufficient to controvert the information furnished by respondent/returned candidate. Similarly the contention of learned senior counsel for the petitioner that the respondent did not pass M.B.A. from Delhi University is also not supported by any cogent and unimpeachable document. Further, in his affidavit, filed in support of his nomination paper in the year 2017, the respondent/returned candidate has not mentioned his M.B.A. degree. It was submitted that even if there was some inaccuracy or incorrect information regarding educational qualification of respondent/returned candidate in the affidavit filed along with the nomination paper, the said act may be punishable under Section 125-A of R.P. Act but it cannot be a basis to contend that it is a corrupt practice. Regarding the case of petitioner that there were electricity dues against the electricity connection of premises no. 109, Rambagh, Allahabad, it was submitted that there is nothing to show that the said arrears were against the respondent/returned candidate. No such document could be brought on record that the said electricity connection was in the name of respondent or that the alleged recovery certificate was issued against the respondent/returned candidate. It was submitted that by learned senior counsel that in the similar way, there is no material to support the averments that the respondent/returned candidate has concealed the fact of housing loan availed by him. It was submitted that even if the allegations made by the petitioner are taken as such, no case of corrupt practice is made out. In support of his contentions, learned senior counsel has referred following case laws :-

(a) *Podipireddy Atchuta Desai v. Chinnam Joga Rao & Ors.*, 1987 (Supp) SCC 42

(b) *State of U.P. And Ors v. Netrapal Singh And Ors.*, 2004 (4) SCC 748

(c) *Dhartipakar v. Rajiv Gandhi*, AIR 1987 SC 1577

(d) *Suresh Seth v. Commr. Indore Municipal Corp.*, 2005 (13) SCC 287

(e) *P.H. Pandian v. P. Veldurai*, 2013(14) SCC 685

(f) *Kashi Nath Mishra v. Vikdramaditya Pandey*, 1998 (8) SCC 735

- (g) Mundrika Singh Yadav v. Shiv Bachan Yadav, 2005 (12) SCC 211
- (h) C.M. Arunugam v. S. Raj Gopal, 1976 (1) SCC 863
- (i) Prem Pal Singh And Ors. v. Rakesh Babu, Manu/UP 0569/2020, decided 03.03.2020
- (j) Chandra Mohan Shukla v. Anil Dhirubhai Ambani And Ors., 2010 (10) ADJ 63
- (k) Union of India v. Association for Democratic Reforms And Anr., AIR 2002 SC 2112
- (l) Peoples Union for Civil Liberties (PUCL) v. Union of India, AIR 2003 SC 2363
- (m) Kuldeep Nayar And Ors. v. Union of India And Ors., 2006(7) SCC 1

12. I have considered rival submissions and perused the record as well as case laws referred by learned counsel for the parties.

13. Before proceeding further it would be pertinent to mention that the election of the respondent is being challenged by the petitioner on the following grounds:-

- A. Because the result of the election, insofar as it concerns the returned candidate, has been materially affected by improper acceptance of nomination paper of respondent in non-compliance of the provisions of Section 33 of the Act.
- B. Because the respondent committed corrupt practice under Section 123(2) of the said Act by interfering in free exercise of the electoral rights of the electors by not disclosing his liabilities as well as correct educational qualification in his affidavit of nomination paper.
- C. Because the respondent committed the corrupt practice under Section 123(4) of the said Act by publishing a false statement of fact, which he believed to be false, and did not believe to be true, regarding his own personal character and conduct, such statement being a statement reasonably calculated to prejudice the prospects of the respondent's own election.
- D. Because the election of the respondent is void, and is liable to be declared void, due to improper acceptance of his nomination paper and also due to commission of corrupt practice by him, as defined under Sections 123(2) and 123(4) of the said Act."

14. In case of Sheodhan Singh v. Mohan Lal (*supra*) Hon'ble Apex Court held that the decision of the question whether corrupt practice was committed by the respondent or not, would not be academic and the court would have to decide the same and thus, where allegations of corrupt practices are involved the petition can not be dismissed as infructuous. In case of Loknath Padhan v. Birendra Kumar Sahu (*supra*), Hon'ble Apex Court observed that a Court should not undertake to decide an issue, unless it is a living issue between the parties and pointed out that if an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, it would be waste of public time and indeed not proper exercise of authority for the Court to engage itself in deciding it. It was held that an academic question, the answer to which cannot affect the position of one party or the other or which has no bearing on some right or liability in controversy between the parties, will be unnecessary and inexpedient to be decided and the Court would properly decline to decide. With reference to the election dispute before it in that case involving alleged disqualification of the returned candidate due to subsistence of five Government contracts with the Government of Orissa, the Apex Court held that even if it is found that the candidate was so disqualified, it would have no factual consequence, as invalidation of election after dissolution of the House would be meaningless and ineffectual and as it would have no consequences operating in future, as it is the only facts existing on the date of nomination that would have relevance. However, Hon'ble Apex Court distinguished the cases in which allegations of corrupt practices are involved in view of Section 8-A of R. P. Act under which a person found guilty of corrupt practices by an order under Section 99 R.P. Act will incur

electoral disqualification up to six years from the date of the order in that regard. It was observed by the Hon'ble Apex Court that the position might be different if the allegation against the respondent were of corrupt practice. If the respondent is found guilty of corrupt practice during the election, not only his election would be declared void, but he would also incur certain electoral disqualifications. Section 8A R.P. Act provides that a person found guilty of a corrupt practice by an order under Section 99 R.P. Act shall be disqualified for a period of six years from the date on which, that order takes effect. The purity of elections is of utmost importance in a democratic set up and the law, has, therefore, taken serious note of corrupt practice in elections and laid down a disqualification for a period of six years on an order being made by the High Court recording a finding of corrupt practice at the time of disposing of the election petition. It is, therefore, obvious that when a corrupt practice is charged against the respondent in an election petition, the trial of the election petition must proceed to its logical end but the principle was held by the Apex Court to be not applicable to disqualification, which has no other consequence than that of making the particular election void and which does not entail any electoral disqualification for the future. In that case, in view of the dissolution of the Legislative Assembly, the Apex Court considered the question of disqualification to be purely academic and dismissed the appeal against the decision in the election petition as futile. In case of PremPal Singh Vs Vs Satyapal Singh (*supra*), this Court has reiterated the position that an academic question, the answer to which cannot affect the position of one party or the other or which has no bearing on some right or liability in controversy between the parties, will be unnecessary and inexpedient to be decided and the Court must decline to decide the same. However, the cases in which allegations of corrupt practices are involved in view of Section 8-A of R. P. Act under which a person found guilty of corrupt practices by an order under Section 99 will incur electoral disqualification, the trial of an election petition must proceed to its logical end.

15. In case of Sohan Lal *Vs* Asha Ram and Ors (1981) 1 SCC 106, the Apex Court disposed of an election appeal without adjudication due to dissolution of the Assembly, fresh elections having taken place and a fresh House coming into existence notwithstanding any substantial grievance for the election petitioner, as the subsequent events rendered the litigation wholly unreal making it waste of the Court's time to consider the issues.

16. In Podipireddy Atchuta Desai *vs.* Chinnam Joga Rao and others (*supra*), the Apex Court has held as under:-

"The question raised in this election appeal are of some importance. We also see the force of the submissions urged on behalf of the appellant. All the same, having regard to the fact that fresh elections have already taken place and the appeal has become redundant in that sense, we will be undertaking a futile exercise if we examine the validity or otherwise of the view taken by the High Court in dismissing the election petition. Under the circumstances without expressing any views, one way or the other, on the validity or otherwise of the decision of the High Court, we direct that this appeal shall stand disposed of with no order as to costs."

17. In Kashi Nath Mishra *vs.* Vikramaditya Pandey and others, (*supra*) an appeal was filed before the Apex Court from the Election Petition No.4 of 1991 filed under Section 81 of Representation of the People Act, 1951. The appellant had challenged the election of the second respondent to the U.P. Legislative Assembly from the 227 Ballia Assembly Constituency in District Ballia. That petition was dismissed. The term of the assembly has expired by efflux of time and thereafter, another election has been held and another Assembly constituted. Under these circumstances, the appeal was dismissed having become infructuous. Similar was the decision of another three-Judge Bench of the Apex Court in Romesh v. Ramesh K. Rana and others (2000) 9 Supreme Court Cases 265, wherein the request was for recount of votes without any allegations of commission of any corrupt practice and in the meanwhile the Assembly itself was dissolved. The Apex Court considered that nothing further survives for consideration and dismissed the election appeal.

18. In the case of *Dhartipakar Vs Rajiv Gandhi* (supra), wherein the allegation with regard to corrupt practice was raised, Hon'ble Supreme Court observed that since allegation was with regard to corrupt practice and the matter is stale and academic but it may be heard. It was observed that "in fact, during the course of hearing the appellant himself stated before us more than once, that it would now every difficult for him to produce evidence to substantiate the allegations of corrupt practice but nonetheless he insisted for the appeal being heard on merit. Though the matter is stale and academic yet having regard to the present state of law, we had to hear the appeal at length." It was further observed by the Hon'ble Apex Court as under:

"The aforesaid allegations do not amount to any corrupt practice as contemplated by Section 123 of the Act. At best these allegations raise a grievance that the Presiding Officers did not perform their duties in accordance with law in as much as they failed in their duty to remove the post- ers and other propaganda material from the polling booth and the hand which was the election symbol of Rajiv Gandhi and the same was displayed within 100 meters of the polling booth in violation of the rules. The allegations do not make out any charge of corrupt practice. If at all the allegations could be a ground under Section 100(1)(d)(iv) of the Act for setting aside election on the ground of its being materially affected but no such plea was raised. Paragraphs 54 to 58 do not deal with any corrupt practice. The above scanning of the election petition would show that the appellant failed to plead complete details of corrupt practice which could constitute a cause of action as contemplated by Section 100 of the Act and he further failed to give the material facts and other details of the alleged corrupt practices. The allegations relating to corrupt practice, even if assumed to be true as stated in the various paragraphs of the election petition do not constitute any corrupt practice."

From above referred case it is clear that the when the term of disputed election has expired and thereafter fresh election have taken place and if the allegations made by the petitioner do not amount to any corrupt practice as contemplated by Section 123 of the Act, the petition could be dismissed. It was observed that at best these allegations raise a grievance that the Presiding Officers did not perform their duties in accordance with law. In the said case Apex Court had dismissed the appeal holding that the appellant cannot be permitted to waste the court time with permission to amend the appeal.

19. In *Mundrika Singh Yadav vs. Shiv Bachan Yadav and others* ((2005) 12 SCC 211), an election petition under Sections 80 and 80-A of the Representation of the People Act, 1951 filed by the appellant was dismissed by the High Court. In the above said election petition, the appellant had sought for the relief of recount of ballot papers. The High Court on trial found a case in that regard having not been made out. The election to the Bihar State Assembly forming subject-matter of the election petition was held in the year 2000. The term of the Legislative Assembly was over. Fresh elections were being held. Under these circumstances, the Apex Court has held that no relief could be allowed to the appellant in this appeal even if this appeal is allowed. The appeal was rendered infructuous and was dismissed accordingly.

20. Thus, it clearly emerges from the above referred cases that the well settled practice is that a Court should not undertake to decide an issue, unless it is a living issue between the parties. If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties, it would be waste of public time and indeed not proper exercise of authority for the Court to engage itself in deciding it. However, the Hon'ble Apex Court has distinguished the cases in which allegations of corrupt practices are involved in view of Section 8-A of R. P. Act under which a person found guilty of corrupt practices by an order under Section 99 will incur electoral disqualification up to six years from the date of the order in that regard. In such a case the trial of an election petition must reach to its logical end but that principle was also held by the Hon'ble Apex Court to be not applicable to disqualification, which has no other consequence than that of making the particular election void and which does not entail any electoral disqualification for the future. In that case, in view of the dissolution of the Legislative Assembly, the

question of disqualification to be purely academic and the decision in the election petition would be futile. Thus, in cases where the allegations of corrupt practices are involved in view of Section 8-A of R. P. Act under which a person found guilty of corrupt practices by an order under Section 99 will incur electoral disqualification for future up like bar to contest election for six years from the date of the order, the election petition may proceed further despite the fact that the term of the returned candidate, for which he was elected, is over and the Assembly has been dissolved and fresh election have also been held.

21. Coming to the facts of the present case, it may be mentioned that so far the ground 'A' mentioned in the election petition to the effect that the election of the returned candidate, has been materially affected by improper acceptance of nomination paper of respondent in non-compliance of the provisions of Section 33 of the R. P. Act, is concerned, on dissolution of the Assembly, the relief sought on ground of improper acceptance of nomination paper has been rendered infructuous, Thus, that aspect needs no consideration.

22. Now the matter is to be examined only regarding the grounds mentioned in petition as "B" and "C" and the question is whether the allegations made in the petition would constitute a case of corrupt practice. It is well settled that charge of corrupt practice is in the nature of a criminal charge and has got to be proved beyond doubt and it must be backed by unimpeachable and incontrovertible documentary evidence. The Court must look for serious assurance, unlaying circumstances or unimpeachable documents to uphold the charges of corrupt practices. The pleadings of the election petitioner in his petition should be absolutely precise and clear containing all necessary details and particulars as required by law (vide Dhartipakar Madan Lal Agarwal v. Rajiv Gandhi (1987) Supp. SCC 93 and Kona Prabhakara Rao v. M. Seshagiri Rao (1982) 1 SCC 442). The allegations in the election petition should not be vague, general in nature or lacking of materials or frivolous or vexatious. In this connection a reference may also be made to the case of case of Pradip Buragohain *Versus* Pranati Phukan (2010) 11 SCC 108, where the Hon'ble Apex Court has reiterated the law regarding corrupt practice.

23. Keeping the aforesaid position of law in view, in the instant case it may seen that the first charge regarding alleged corrupt practice against the respondent is that by not disclosing his liabilities as well as correct educational qualification in his affidavit of nomination, he has interfered in free exercise of the electoral rights of the electors. Regarding the alleged liabilities, it was alleged that there were arrears of electricity dues of Rs. 3,00,050/- against the electricity connection installed in the premises of the respondent and a recovery certificate was also issued on 05.10.2016 against that connection and that amount was not paid till the filing of nomination paper by the respondent but in his affidavit of nomination the respondent has stated that there were no electricity dues against him. It would be pertinent to mention that there are no such averment that the said electricity connection is in the name of the respondent or that the alleged recovery certificate was issued against the respondent. Merely because the said electricity connection is installed in the property owned by the respondent, it would not be sufficient to show that the respondent has concealed the alleged liability. No such document could be shown that recovery certificate was issued against the respondent. It was further alleged that the respondent has taken a housing loan from P.N.B., Civil Lines, Allahabad through account number 001200NC00801166 in respect of ½ part of house no. 2, Minto Park House, Kydganj, Allahabad and said loan amount was shown by respondent in his affidavit of nomination in the year 2012 but in nomination in question in the year 2017 he has concealed the said loan amount, whereas said loan has not been paid/cleared till the date of filing of nomination paper by the respondent. In this connection it would be pertinent to mention that no such incontrovertible document of the Bank could be brought on record to show that the alleged loan has not been paid till the date of nomination. Merely a vague statement has been made that the respondent has not cleared his loan. Here it would be pertinent to mention that in case of Kisan Shankar Kathore (*supra*), Hon'ble Apex Court held as under :

"Insofar as non-disclosure of the electricity dues is concerned, in the given facts of the case, we are of the opinion that it may not be a serious lapse. No doubt, the dues were outstanding, at the same time, there was a bona fide dispute about the outstanding dues in respect of the first electricity meter. It would have been better on the part of the appellant to give the information along with a note about the dispute, as suggested by the High Court, we still feel that when the appellant nurtured belief in a bona fide manner that because of the said dispute he is not to give the information about the outstanding amount, as it had not become 'payable', this should not be treated as a material lapse. Likewise, as far as the second electricity meter is concerned, it was in the premises which was rented out to the tenants and the dues were payable by the tenants in the first instance. Again, in such circumstances, one can bona fide believe that the tenants would pay the outstanding amount. No doubt, if the tenants do not pay the amount the liability would have been that of the owner, i.e. the appellant. However, at the time of filing the nomination, the appellant could not presume that the tenants would not pay the amount and, therefore, it had become his liability. Same is the position with regard to non-payment of a sum of Rs.1,783/- as outstanding municipal dues, where there was a genuine dispute as to revaluation and reassessment for the purpose of assessing the taxes was yet to be undertaken. Having said so, we may clarify that it would depend in the facts and circumstances of each case as to whether such a non-disclosure would amount to material lapse or not. We are, thus, clarifying that our aforesaid observation in the facts of the present case should not be treated as having general application.

In the above referred case the returned candidate has not disclosed his several assets and dues and one of them was regarding concealment of electricity dues. Hon'ble Apex Court has clarified that it would depend in the facts and circumstances of each case as to whether such a non-disclosure would amount to material lapse or not. In the present case there is no documentary evidence that the said electricity connection was in the name of the respondent or that the alleged recovery certificate was issued against the applicant. Further, in the above referred case no issue of corrupt practice was involved. There is no such finding that concealment of electricity dues would amount to corrupt practice contemplated under section 123 of the R. P. Act. Even on the premises of the said case law the allegation regarding non-disclosure of electricity dues and loan amount would not amount to corrupt practice. It would be relevant to mention here that in case of *Kuldip Nayar V UOI (supra)*, Hon'ble Apex has referred case of *Union of India V Assn. for Democratic Reforms (2002) 5 SCC 294*, wherein it was held that holding of any asset (immovable or moveable) or any educational qualification is not the eligibility criteria to contest election. Considering the said legal position and peculiar facts and circumstances of the case, the said allegations, regarding concealment of electricity dues or housing loan, made by the petitioner can hardly be termed as corrupt practice within the meaning of section 123 of the R.P. Act.

24. So far the allegations regarding false information about the educational qualification in the affidavit the respondent, filed along with nomination form is concerned, it was alleged that earlier the respondent has contested election of Legislative Assembly from the same constituency in the year 2007, wherein he has shown his educational qualification as B.Tech. from University of Shefield, England passed in the year 2003 and the highest degree was shown "Master of Finance and Control" from Delhi University in the year 2006. The respondent again contested election from the said Assembly Constituency in the year 2012, wherein same educational qualifications and degrees were shown but while filing his nomination for election from same constituency in the year 2017, the respondent has shown his qualification and highest degree as B.Tech. from Seferred University, England, passed in the year 2007, whereas there is no university by the name of "Seferred" in England. It was stated that there is university of Shefield in England, which awards degree of B.E. in Chemical Engineering and not the degree of B.Tech. Further, in his nomination paper in the year 2007 and 2012 he has mentioned that he has degree of M.B.A. from Delhi University passed in the year 2006, whereas in the nomination paper of 2017 he has shown his B.Tech. degree in the

year 2007 and thus if he has passed the degree of M.B.A. from University of Delhi in the year 2006, he can not pass B.Tech. examination from England in the year 2007, which is a two years course. It was submitted that in fact, the respondent has not cleared the alleged M.B.A. degree from University of Delhi. Further, in the year 2007 and 2012 in his affidavit/nomination paper, he has claimed that he passed B.Tech. degree in the year 2003 from Shefield University, England but his name has not been shown in the Alumni of 2003 of the said University and all these facts go to show that respondent did not obtain the alleged degree of B.Tech from University of Shefield, England and he has given false information in his affidavit/nomination paper. It was submitted that respondent was under legal obligation to disclose correct facts in his affidavit filed along with nomination form as it was for the information of electors to know personal character and conduct of the candidate and thus there was substantial defect in his nomination paper.

25. It may be stated that the error in spelling of Shefield University is hardly a matter of consideration. Similarly the error or inconsistency regarding the issue whether the respondent passed the degree of B. Tech in the year 2003 or 2007 would not be a material concealment unless and until it is shown that the respondent does not hold the said degree of B. Tech. from that University at all. In this connection only it was alleged that Shefield University does not awards degree of B. Tech., rather it awards the degree of B.E. and that the name of respondent has not been shown in the list of Alumni of the said University. These allegations are hardly sufficient to doubt the degree of B. Tech., which the respondent claims to hold and mentioned in the affidavit filed along with nomination form. No authoritative document issued by the said university or any other unimpeachable document was filed to show that the respondent did not pass the alleged degree from that university.

26. There is no doubt in preposition that every candidate has to disclose the relevant information in his affidavit. In *Resurgence India v. Election Commission of India and Anr.* (*supra*), the Apex Court held that every candidate is obligated to file an affidavit with relevant information with regard to their criminal antecedents, assets and liabilities and educational qualification. The fundamental right under Article 19 (1) (a) of the voter was reiterated in the said judgment and it was held that filing of affidavit with blank particulars would render the affidavit as nugatory. Similarly in *Kisan Shankar Kathore v. Arun Dattatray Sawant* (*supra*), the Hon'ble Apex Court considered the question as to whether it was incumbent upon the Appellant to have disclose the information sought for in the nomination form and whether the non-disclosure thereof render the nomination invalid and void. It was observed as under :

"When the information is given by a candidate in the affidavit filed along with the nomination paper and objections are raised thereto questioning the correctness of the information or alleging that there is non-disclosure of certain important information, it may not be possible for the returning officer at that time to conduct a detailed examination. Summary enquiry may not suffice. Present case is itself an example which loudly demonstrates this. At the same time, it would not be possible for the Returning Officer to reject the nomination for want of verification about the allegations made by the objector. In such a case, when ultimately it is proved that it was a case of non-disclosure and either the affidavit was false or it did not contain complete information leading to suppression, it can be held at that stage that the nomination was improperly accepted. Ms. Meenakshi Arora, learned senior counsel appearing for the Election Commission, right argued that such an enquiry can be only at a later stage and the appropriate stage would be in an election petition as in the instant case, when the election is challenged. The grounds stated in Section 36(2) are those which can be examined there and then and on that basis the Returning Officer would be in a position to reject the nomination. Likewise, where the blanks are left in an affidavit, nomination can be rejected there and then. In other cases where detailed enquiry is needed, it would depend upon the outcome thereof, in an election petition, as to whether the nomination was properly accepted or it was a case of improper acceptance. Once it is found that it was a case of improper acceptance, as there was misinformation

or suppression of material information, one can state that question of rejection in such a case was only deferred to a later date."

In the said case there were several concealments and non-disclosure about assets and liabilities of the returned candidate and his nomination was improperly accepted by the Returning Officer and thus his election was set aside by the High Court on the grounds contemplated in section 100(1)(d) of R.P. Act and appeal was dismissed by the Apex Court. However in the instant case the relief sought on ground of improper acceptance of nomination papers has already been rendered as infructuous. Further, in view of attending facts and circumstances of the case it appears that the alleged inaccuracy or inconsistency in the affidavit regarding educational qualification of the respondent / returned candidate were not of substantial character. As observed earlier, the petitioner has not filed any such authoritative document of said the University or any other unimpeachable document, which could show that the respondent did not pass the alleged degree of B. Tech.. In view of these facts and circumstances the defects in disclosure, alleged by the petitioner, can not be considered to be of substantial character, so as to be termed as a corrupt practice within the meaning of Section 123 of the Representation of People Act.

27. In case of Bhikaji Keshao Joshi (supra), the election petition, having inter-alia allegations of corrupt practice, was dismissed by the Tribunal on technical grounds including the infirmity in verification of pleadings but in appeal, the Hon'ble Apex Court referred back the case to the Tribunal for due enquiry and it was observed as under :

"Having regard to the nature of the alleged disqualification, which is substantially to the effect that the returned candidate had interest in contracts with the Government at the relevant dates, it was very necessary that the matters should have been cleared up in the enquiry before the Election Tribunal. It is not in the interest of purity of elections that such allegations of disqualification should be completely ignored without enquiry and it appears rather surprising that the Tribunal should have ignored them and exercised its power to dismiss the petition. However reluctant we might be to interfere in a matter like this after the lapse of three years and four months and with only an year and eight months before the general elections, we feel constrained to send this matter back for due enquiry. But before doing so and in view of the delay and other circumstances that have already happened, we, in exercise of the powers which the Tribunal in the normal course might itself have exercised, direct the striking out of all the items of alleged corrupt practices set out in Schedule A excepting the one covered by paragraph I of item 1"

In the above referred case the petition was dismissed on technical grounds and the term of the returned candidate as member of Assembly was still subsisting and thus, the issue between the parties was quite alive.

28. Here it would be pertinent to mention that in case of Peoples Union for Civil Liberties V UOI (supra), the Apex Court held as under:

"The last item left for discussion is about educational qualifications. In my view, the disclosure of information regarding educational qualifications of a candidate is not an essential component of the right to information flowing from Article 19(1)(a). By not providing for disclosure of educational qualifications, it cannot be said that the Parliament violated the guarantee of Article 19(1)(a). Consistent with the principle of adult suffrage, the Constitution has not prescribed any educational qualification for being Member of the House of the People or Legislative Assembly. That apart, I am inclined to think that the information relating to educational qualifications of contesting candidates does not serve any useful purpose in the present context and scenario. It is a well known fact that barring a few exceptions, most of the candidates elected to Parliament or the State Legislatures are fairly educated even if they are not Graduates or Post-Graduates. To think of

illiterate candidates is based on a factually incorrect assumption. To say that well educated persons such as those having graduate and postgraduate qualifications will be able to serve the people better and conduct themselves in a better way inside and outside the House is nothing but overlooking the stark realities. The experience and events in public life and the Legislatures have demonstrated that the dividing line between the well educated and less educated from the point of view of his/her calibre and culture is rather thin. Much depends on the character of the individual, the sense of devotion to duty and the sense of concern to the welfare of the people. These characteristics are not the monopoly of well educated persons. I do not think that it is necessary to supply information to the voter to facilitate him to indulge in an infructuous exercise of comparing the educational qualifications of the candidates. It may be that certain candidates having exceptionally high qualifications in specialized field may prove useful to the society, but it is natural to expect that such candidates would voluntarily come forward with an account of their own academic and other talents as a part of their election programme. Viewed from any angle, the information regarding educational qualifications is not a vital and useful piece of information to the voter, in ultimate analysis. At any rate, two views are reasonably possible. Therefore, it is not possible to hold that the Parliament should have necessarily made the provision for disclosure of information regarding educational qualifications of the candidates".

From the above referred case it appears that the information regarding educational qualifications of a candidate is not a vital and useful piece of information to the voter, in ultimate analysis. Considering the ratio of the said case law, it cannot be said that any inconsistency or error in the affidavit of a candidate regarding his educational qualification would amount to corrupt practice.

29. In case of Mairembam Prithviraj (supra), Hon'ble Apex Court held that every voter has a fundamental right to know about the educational qualification of a candidate. It is also clear from the provisions of the Act, Rules and Form 26 that there is a duty cast on the candidates to give correct information about their educational qualifications. In that case it was not in dispute that the Appellant did not study MBA in the Mysore University. It was the case of the Appellant that reference to MBA from Mysore University was a clerical error. It was contended by the Appellant that he always thought of doing MBA by correspondence course from Mysore University but actually he did not do the course. The Appellant contested election to the same constituency in 2008 and in the affidavit filed by him in Form 26 he declared that he passed MBA from Mysore University in 2004. It was held that the false declaration relating to his educational qualification cannot be stated to be not of a substantial character. It is no more res integra that every candidate has to disclose his educational qualification to subserve the right to information of the voter. It was held that having made a false declaration relating to his educational qualification, the Appellant cannot be permitted to contend that the declaration is not of a substantial character. However, in the instant case, as observed earlier, the petitioner could not produce any such cogent material or unimpeachable document that the respondent does not hold alleged B.Tech. degree or that the respondent did not pass the said degree at all. Further, in the instant matter the material question is whether a case of corrupt practice is made out against the respondent and the issue of corrupt practice was not discussed in that case. As held in case of Pradip Burgohain (supra) the onus of proof of the allegations made in the election petition is undoubtedly on the person who assails an election. A charge of corrupt practice is in the nature of a criminal charge and the pleadings of the election petitioner in his petition should be absolutely precise and clear containing all necessary details and particulars as required by law but in the instant case the petitioner could not produce any such unimpeachable document, which could show that the respondent did not pass the alleged degree. Further, even in the case of Mairembam Prithviraj (supra), no such preposition was laid down that the defect in disclosure of information regarding education of the candidate would amount to corrupt practice.

30. In case of Kisan Shankar Kathore (*supra*) the election of the returned candidate was successfully challenged on the ground of non-disclosure of material information. The appeal filed by the returned candidate was dismissed by the Court by observing as follows:

"Once it is found that it was a case of improper acceptance, as there was misinformation or suppression of material information, one can state that question of rejection in such a case was only deferred to a later date. When the Court gives such a finding, which would have resulted in rejection, the effect would be same, namely, such a candidate was not entitled to contest and the election is void."

However, in the present case, as discussed above, due to dissolution of the Assembly, the relief of declaration of election as void, has become infructuous and thus can not be granted. The issue whether any incorrect or false information regarding education of candidate would amount to corrupt practice was not discussed in the said case. Thus, the above referred case also does not help the petitioner.

31. Learned Senior Counsel for the petitioner has also referred case of Shaligram Shrivastava (*supra*), wherein the nomination of one of the candidate was rejected on ground of non-submission of the required declaration and it was held by the Hon'ble Apex Court since such information is necessary and relevant for the purpose of scrutiny of the nomination paper under Section 36(2), in the light of Section 8 of the Act, it can well be furnished on a format provided to the candidate by the Returning Officer and it becomes his duty to furnish such information so that a Returning Officer may discharge its statutory duty to scrutinize the nomination paper effectively, properly and in consonance with the provisions of law. In that case the candidate had failed to furnish such information as sought on the proforma given to him and had also failed to be present personally or through his representative at the time of scrutiny and thereby the statutory duty/power of Returning Officer for holding proper scrutiny of nomination paper was rendered nugatory and thus, upholding the rejection of nomination of said candidate, appeal was dismissed. However, in that case too, no issue relating to corrupt practice was involved. Thus, said case has no relevance for deciding the issue involved in the present case.

32. In the instant case, as discussed above, the question for consideration is whether a case of corrupt practice is made out, as for other purposes the petition has been rendered infructuous. None of the case law relied by learned Senior counsel for the petitioner addresses the issue that any incorrect or even the false information in the affidavit regarding education of the candidate would fall within the ambit of "corrupt practice". As stated earlier, the petitioner also could not show any such unimpeachable and incontrovertible document that the respondent does not hold the alleged degree of B.Tech. at all. Considering the ratio of law laid down by the Hon'ble Supreme Court in case of Peoples Union for Civil Liberties V UOI (*supra*) as well as Kuldip Nayar (*supra*), the anomalies regarding educational qualification shown in affidavit of respondent or to say even false information regarding education of the respondent, can hardly be termed as "corrupt practice" within the meaning of sub section (2) or (4) of section 123 R.P. Act. Further, for the sake of argument even if it is assumed that the respondent does not hold the degree of MBA, which was shown by him in his affidavit filed in nomination of election to the said constituency in the year 2012, it can not be a ground hold that it would constitute a corrupt practice in respect of next election in the year 2017. In his affidavit filed along with his nomination form for election in the year 2017, the respondent has not mentioned the degree of M.B.A. Some false information regarding education of the respondent in his nomination form in some earlier election, can not be a ground to hold that respondent committed corrupt practice in the subsequent election.

33. Another ground taken in the petition is that during campaign in the election, the respondent got printed pamphlets and hand bills, in which he mentioned his name as Er. Harsh Vardhan Bajpayee and he posed himself as qualified Engineer, where as he did not hold degree in Engineering and thus, it amounts to

corrupt practice of undue influence. It was submitted that in the constituency in question most of the electors are well educated and comprise a numbers of doctors, engineers, professors and advocates etc. and the voters want to elect a well educated person to represent them and thus, incorrect disclosure of educational qualification and non-disclosure of government dues would constitute corrupt practice of undue influence.

34. As observed earlier, the petitioner could not show any such unimpeachable and incontrovertible document that the respondent did not pass the said degree of B. Tech. from the alleged University and that the inaccuracy or inconsistency regarding the educational qualification of respondent in his affidavit are not of substantial character. Further, the allegations made by the petitioner are vague and general. No specific details have been mentioned that when and where and in what manner the respondent represented himself as an educated Engineer or that the electors have voted in his favour due to that reason and thereby respondent employed corrupt practice of undue influence. Only general averments have been made that during campaigning in the election, the respondent got printed pamphlets and hand bills mentioning himself as Engineer and that as the most of the electors in the constituency are well educated and comprise a numbers of doctors, engineers, professors and advocates etc. and thus, the false representation of the respondent as Engineer acted favourably to him and adversely prejudiced the prospects of the petitioner. In the absence of any specific averments, the said allegation appears hypothetical. As stated earlier, the allegations of corrupt practice are in the nature of criminal charge and there should be no any vagueness in the allegations so that the returned candidate may know the case he has to meet. If the allegations are vague and general and the particulars of corrupt practice are not stated in the pleadings, the trial of the election petition cannot proceed for want of cause of action. The emphasis of law is to avoid a fishing and roving inquiry. The pleadings of the election petitioner in his petition should be precise and clear containing all necessary details and particulars as required by law (*Dhartipakar Madan Lal Agarwal v. Rajiv Gandhi* (1987) Supp. SCC 93 and *Kona Prabhakara Rao v. M. Seshagiri Rao* (1982) 1 SCC 442). In the case in hand, neither there is any such incontrovertible and unimpeachable document, which could show that the respondent did not hold the alleged degree in Engineering/Technology nor there are specific allegations that how alleged incorrect and false statement of facts favourably prejudiced the prospects of his election. Considering all these facts of the matter, the inaccuracy or concealment regarding educational qualification of the respondent did not amount to unduly influencing the voters, as the defect in disclosure was not of substantial character that could have materially prejudiced the prospects of the election, for it to be termed as a corrupt practice within the meaning of Section 123 of the Representation of People Act.

35. Learned senior counsel for both the parties have referred the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of *P. H. Pandian v. P. Veldurai and another*, (supra), where an appeal under Section 116-A of the R. P. Act of 1951 was filed questioning the judgment made in the election petition, it was observed by the Hon'ble Supreme Court that though fresh elections have since been held to Tamil Nadu Legislative Assembly and to an extent the appeal has been rendered infructuous, the manner in which the election petition was dealt with by the High Court causes concern and necessitates. In the said case, Hon'ble Apex Court made reference to some salient facts but it was observed that it is settled practice of Supreme Court not to pronounce upon matters which are only of an academic interest. Once the charge of corrupt practice fails, rest of the appeal would be rendered infructuous because fresh elections have already taken place and the old assembly is no longer in existence. It was further observed that even if the appellant therein was to succeed on the issue that the returned candidate had a subsisting contract with the Panchayat Union and the State Government and was, therefore, disqualified to be chosen for the seat under Section 9-A of the Act of 1951, it would only be of an academic interest. It was observed that appeal for all intent and purposes has been rendered infructuous and thus, appeal was disposed of. It is apparent that this case law hardly supports the case of petitioner.

36. After considering all relevant facts of the matter and the law applicable thereto it clearly emerges that the averments contained in the election petition do not amount to any corrupt practice and at the most the same relate to irregularities and illegalities alleged to have been committed by the respondent, which would at best be relevant if there was further allegation that it materially affected the result of the election. The averments contained in paras 32 to 38 and 40 to 46 containing narration of facts about corrupt practice do not make out any corrupt practice so as to require any further adjudication on merits of the matter. These allegations even if assumed to be true do not make out any case of commission of corrupt practice as enshrined in subsection (2) or (4) of section 123 of R. P. Act. From the law laid down in case of *Dhartipakar Vs Rajiv Gandhi* (supra) it is clear that if the allegations made by the petitioner do not amount to any corrupt practice as contemplated by Section 123 of the R. P. Act and the period for which the respondent was elected is already over and fresh elections have taken place, the petition could be dismissed.

37. It may be pointed out that the petitioner has sought the relief to declare the election of respondent as Member of Legislative Assembly from 262 Allahabad City North Assembly Constituency, District Allahabad, as null and void and set aside the same. The term of the Assembly, for which the respondent was elected, is already over and the Assembly has been dissolved by efflux of time and that fresh Legislative Assembly has been constituted. Though allegations of corrupt practice were levelled against the respondent but the same are not supported by material facts and unimpeachable documents, apart from the fact that the said allegations do not amount to corrupt practice as contemplated by section 123 of the R. P. Act. In view of these facts the relief claimed by the petitioner has been rendered infructuous. As observed earlier, it is the consistent view of the Hon'ble Supreme Court that the time of the Court is precious one and academic exercise is not warranted unless still some relief may be granted to petitioner may be followed. Therefore, this Court finds that there is no impediment or obstacle in dismissing the election petition, as the prayer itself has become infructuous. In view of the aforesaid discussion and in the light of the settled law of the Hon'ble Supreme Court, this Court is of the considered view that nothing further survives in this matter. Accordingly, the election petition is liable to be dismissed as having been rendered infructuous.

38. In view of aforesaid, the application No. 19 of 2022 filed by the respondent is allowed and the objections/application No. 20 of 2022 filed by the petitioner stand rejected. The election petition is dismissed as infructuous. No order as to costs.

(Sd.) RAJ BEER SINGH, J.

Order Date :- 12.09.2022.

Anand

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 21 अक्टूबर, 2022 ई०
29 आश्विन, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं० 82/उ०प्र०-लो०स०/13/2019 (इलाज)-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2019 की निर्वाचन याचिका संख्या 13 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 09 सितम्बर, 2022 के निर्णय को एतद्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,
 अमित कुमार,
 सचिव,
 भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 21st October, 2022
29th Asvina, 1944 (Saka).

NOTIFICATION

No. 82/UP-HP/13/2019 (Alld.)—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 9th September, 2022 of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in Election Petition No. 13 of 2019.

By order,
AMIT KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Election Petition No. 13 of 2019

(Under Sections 80, 80-A/81 of Representation of the People Act, 1951)

District : Badaun.

Sri Dinesh Kumar, S/o Bhukan Singh,
Resident of A-26, Awas Vikas Colony,
District – Badaun.

... Election Petitioner

Versus

Dr. Sanghmitra Maurya D/o Shri Swami Prasad Maurya,
Resident of 6/237, E-Vipul Khand, Gomti Nagar,
District – Lucknow-226010.

... Respondent

Court No. - 3**Case :- ELECTION PETITION No. 13 of 2019**

Petitioner :- Shri Dinesh Kumar

Respondent :- Sanghmitra Maurya

Counsel for Petitioner :- Saurabh Yadav, Dinesh Kumar (In Person)

Counsel for Respondent :- Udayan Nandan, Chandan Sharma, Vinod Kumar Kushwaha

Hon'ble Surya Prakash Kesarwani, J.

Heard Sri Saurabh Yadav, learned counsel for the Election Petitioner and Sri Udayan Nandan, learned counsel for the respondent.

Election petitioner has filed a Withdrawal Application No. 26 of 2022, praying that the Election Petition may be dismissed as withdrawn.

On the aforesaid withdrawal application this Court passed the following order on 20.05.2022:-

"Heard Sri Shivam Yadav alongwith Sri Saurabh Yadav, learned counsel for the Election Petitioner and Sri Udayan Nandan, learned counsel for the respondent - winning candidate. The Election Petitioner has filed a Civil Misc. Withdrawal Application No. 26 of 2022 dated 11.05.2022. In paragraphs 2, 3 and 4 of the withdrawal Application the Election Petitioner has stated as under :-

"2. That the above noted petition has been filed by the petitioner challenging the Election of the respondent on various grounds mentioned in the petition itself, however, the petition is pending since year 2019 and with the change of political circumstances and scenario, the petitioner do not wish to pursue the present petition any further, the aforesaid decision has been taken by the petitioner without any pressure or coercion upon him and it is out of free will the present affidavit is being filed before this Hon'ble Court.

3. That it is for this reason the petitioner want to withdraw the election petition, the present election petition therefore be allowed to be withdrawn and the same may be dismissed as withdrawn so that justice be made.

4. That it is therefore most respectfully prayed that this Hon'ble Court may be pleased to dismiss the aforesaid Election Petition No. 13 of 2019, as withdrawn without prejudice to the rights of respondents in the interest of justice, otherwise, the applicant shall suffer irreparable loss and injury."

Section 109 of the Representation of the People Act, 1951 provides as under :-

"109 Withdrawal of election petitions -

(1) An election petition may be withdrawn only by leave of the High Court.

(2) Where an application for withdrawal is made under sub-section (1), notice thereof fixing a date for the hearing of the application shall be given to all other parties to the petition and shall be published in the Official Gazette."

Issue notice fixing 15.07.2022 for hearing on the withdrawal application, which may also be published in the official gazette.

Steps be taken by the Election Petitioner within a week."

In compliance to the aforesaid order, notices were issued and publication has also been made in the Government Gazette Uttar Pradesh on 04.06.2022. Copy of the Gazette has been filed by the Election - Petitioner alongwith compliance affidavit dated 26.07.2022 being paper No. A - 49.

None has filed any application to oppose the aforesaid withdrawal application.

In view of the aforesaid, the Election Petition is dismissed as withdrawn.

Withdrawal Application No. 26 of 2022 is disposed of.

(Sd.) SURYA PRAKASH KESARWANI, J.

Order Date :- 9.9.2022/vkg

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 21 अक्टूबर, 2022 ई०
29 आश्विन, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं० 82 /उ०प्र०-ल००८० /14 /2019 (इलाज)-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2019 की निर्वाचन याचिका संख्या 14 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 09 सितम्बर, 2022 के निर्णय को एतद्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,
 अमित कुमार,
 सचिव,
 भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 21st October, 2022
29th Asvina, 1944 (Saka).

NOTIFICATION

No. 82/UP-HP/14/2019 (Alld.)—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 9th September, 2022 of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in Election Petition No. 14 of 2019.

By order,
AMIT KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Election Petition No. 14 of 2019

(Under Sections 80, 80-A/81 of Representation of the People Act, 1951)

District : Badaun.

Dharmendra Yadav S/o Shri Abhay Ram,
R/o Village and Post Saifai,
District – Etawah.

... Election Petitioner

Versus

Dr. Sanghmitra Maurya D/o Shri Swami Prasad Maurya,
R/o 6/237, E-Vipul Khand, Gomti Nagar,
District – Lucknow-226010.

... Respondent

Court No. - 3

Case :- ELECTION PETITION No. - 14 of 2019

Petitioner :- Dharmendra Yadav

Respondent :- Sanghmitra Maurya

Counsel for Petitioner :- Shivam Yadav, Dharmendra Yadav (In Person), Narendra Kumar Pandey

Counsel for Respondent :- Udayan Nandan, Chandan Sharma, Vinod Kumar Kushwaha

Hon'ble Surya Prakash Kesarwani, J.

Heard Sri Shivam Yadav learned counsel for the Election Petitioner and Sri Udayan Nandan, learned counsel for the respondent.

Election petitioner has filed a withdrawal application No. 25 of 2022, praying that the Election Petition may be dismissed as withdrawn.

On the aforesaid withdrawal application this Court passed the following order on 20.05.2022:-

"Heard Sri Shivam Yadav alongwith Sri Saurabh Yadav, learned counsel for the Election Petitioner and Sri Udayan Nandan, learned counsel for the respondent - winning candidate. The Election Petitioner has filed a Civil Misc. Withdrawal Application No. 25 of 2022 dated 11.05.2022. In paragraphs 2, 3 and 4 of the withdrawal Application the Election Petitioner has stated as under :-

"2. That the above noted petition has been filed by the petitioner challenging the Election of the respondent on various grounds mentioned in the petition itself, however, the petition is pending since year 2019 and with the change of political circumstances and scenario, the petitioner do not wish to pursue the present petition any further, the aforesaid decision has been taken by the petitioner without any pressure or coercion upon him and it is out of free will the present affidavit is being filed before this Hon'ble Court.

3. That it is for this reason the petitioner want to withdraw the election petition, the present election petition therefore be allowed to be withdrawn and the same may be dismissed as withdrawn so that justice be made.

4. That it is therefore most respectfully prayed that this Hon'ble Court may be pleased to dismiss the aforesaid Election Petition No.14 of 2019, as withdrawn without prejudice to the rights of respondents in the interest of justice, otherwise, the applicant shall suffer irreparable loss and injury."

Section 109 of the Representation of the People Act, 1951 provides as under :-

"109 Withdrawal of election petitions -

(1) An election petition may be withdrawn only by leave of the High Court.

(2) Where an application for withdrawal is made under sub-section (1), notice thereof fixing a date for the hearing of the application shall be given to all other parties to the petition and shall be published in the Official Gazette."

Issue notice fixing 15.07.2022 for hearing on the withdrawal application, which may also be published in the official gazette.

Steps be taken by the Election Petitioner within a week."

In compliance to the aforesaid order, notices were issued and publication has also been made in the Government Gazette, Uttar Pradesh on 04.06.2022. Copy of the Gazette has been filed by the Election - Petitioner alongwith compliance affidavit dated 03.08.2022 being paper No. A - 58.

None has filed any application to oppose the aforesaid withdrawal application.

In view of the aforesaid, the Election Petition is dismissed as withdrawn.

Withdrawal Application No. 25 of 2022 is disposed of.

(Sd.) SURYA PRAKASH KESARWANI, J.

Order Date :- 9.9.2022/vkg

By order,
AMIT KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

पी०एस०य०पी०-36 हिन्दी गजट-भाग 7-ख-2022 ई० |

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी०एस०य०पी०-170 निर्वाचन-02.12.202-75 प्रतियां (डी०टी०पी० / आफसेट)।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 03 दिसम्बर, 2022 ई० (अग्रहायण 12, 1944 शक संवत्)

भाग ८

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, टूण्डला, जनपद फिरोजाबाद
स्व-कर निर्धारण नियमावली

18 नवम्बर, 2022 ई०

शुद्धि-पत्र

सं०/1148/न०पा०प०टूण्डला/2022-23-नगरपालिका परिषद् टूण्डला, फिरोजाबाद अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) के अन्तर्गत एवं नगरपालिका के पत्रांक 1053/न०पा०प० टूण्डला/2022-23 दिनांक 12 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं० 1018/न०पा०प० टूण्डला में प्रकाशित है जो त्रुटिपूर्ण है अर्थात् सरकारी गजट के पृष्ठ सं० 527 पर मुद्रित पिछले विज्ञप्ति का कुछ अंश भूलवश मुद्रित नहीं हो सका है।

अतः क्रम संख्या 3 (द) के पश्चात् छूटे अंश को जोड़ते हुए शुद्ध रूप से पढ़ा व समझा जाय।

04—निर्धारित मासिक किराया दर से कार्पेट एरिया के योग को गुणा करें तथा 12 से गुणा करने पर वार्षिक किराया प्राप्त होगा।

05—आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर दरें, कार्पेट एरिया का 80 प्रतिशत होगा।

06—भवन स्वामी द्वारा भवन में स्वयं निवास करने पर वार्षिक किराया (ए०आर०बी०) में निम्न छूट को घटायें—
(क) दस वर्ष की आयु वाले भवनों में (ए०आर०बी०) को (-) .25 प्रतिशत।

(ख) दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम आयु वाले भवनों में (ए०आर०बी०) को (-) 0.3 प्रतिशत।

(ग) बीस वर्ष से अधिक आयु वाले भवनों में (ए०आर०बी०) को (-) 0.40 प्रतिशत।

(घ) व्यावसायिक भवनों/दुकानों का गृहकर व जलकर नगरपालिका द्वारा अधिकतम निर्धारित दर की 05 गुना अथवा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट अथवा वास्तविक किराये के अनुसार व्यवसायिक भवनों में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

07—यदि भवन किराये पर उठाया गया है जो नियमानुसार अवधारित वार्षिक (ए०आर०बी०) में जोड़ें।

(क) दस वर्ष से अधिक पुराना हो तो 25 प्रतिशत अधिक होगा। (ए०आर०बी०+25) प्रतिशत।

(ख) दस वर्ष से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम पुराना हो तो 12.5 प्रतिशत अधिक होगा। (ए०आर०बी०+१२.५) प्रतिशत।

(ग) बीस वर्ष से अधिक पुराना हो तो यथावत् समझा जायेगा।

08—भवनों में कई मंजिल होने की दशा में प्रत्येक मंजिल का वार्षिक किराया मूल्य उपरोक्त विधि से ही ज्ञात किया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, टूण्डला द्वारा निर्धारित कारपेट एरिया प्रतिवर्ग फुट मासिक किराये की दरें (रुपये में)

भवन की प्रकृति	पक्का मकान (आर०सी०सी० / R.B.B. छत ईट / पत्थर / टाईल एवं सीमेन्ट से जुड़ी दीवार)	अद्व पक्का मकान (ईट / पत्थर / टाईल्स एवं मिट्टी से जुड़ी दीवार)	कच्चा भवन (मिट्टी / पत्थर व मिट्टी से बनी दीवार)	भूमि/ भू-खण्ड में
फर्श की प्रकृति सड़क की चौड़ाई	पत्थर / टाईल्स / पक्का / फर्श मुजाइक	कच्चा फर्श	पत्थर / टाईल्स / पक्का / फर्श मुजाइक	कच्चा फर्श
क—(15 फुट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	1.00	0.50	0.80	0.30
ख—(15 फुट से 10 फुट चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	0.80	0.40	0.60	0.25
ग—(10 फुट से कम चौड़ी सड़क पर स्थित भवन)	0.50	0.25	0.20	0.10
				0.05
				0.05

नोट—

1—यदि किसी करदाता द्वारा जलकर व गृहकर वित्तीय वर्ष में जमा नहीं किया जाता है तो बकाये पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज वसूला जायेगा।

2—जलकर, गृहकर के अतिरिक्त प्रत्येक जल संयोजन शुल्क रु० 1115.00 व जलमूल्य (वाटर चार्ज) पर प्रतिमाह रु० 50.00 की दर से वसूला जायेगा जो जलकर में समायोजित होगा।

3—कर निर्धारण हेतु निर्धारित कारपेट एरिया प्रतिवर्ग फुट मासिक किराये की दरें प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् कारपेट एरिया प्रतिवर्ग फुट मासिक किराये की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

4—कर निर्धारण रजिस्टर में नामान्तरण।

ह० (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, टूण्डला,
जनपद फिरोजाबाद।

कार्यालय नगर पंचायत, बेवर (मैनपुरी)

17 नवम्बर, 2022 ई०

सं० 214 / न०पं०बेवर / उपनियम / 2022-23—उ०प्र० 0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(1)(त्र)(ङ) के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों के अनुसार नगर पंचायत, बेवर, जनपद मैनपुरी अपनी सीमा के अन्दर हेतु नियम / उपविधियां बनायी गयी हैं। जिसमें नगर पंचायत, बेवर की बोर्ड बैठक दिनांक 4 अगस्त, 2022 के प्रस्ताव संख्या 01 सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार करते हुये पारित किया गया है। तदनुसार कार्यालय के पत्र संख्या 203 / न०पं०बेवर / उपनियम / 2022-23 दिनांक 13 अक्टूबर, 2022 को उक्त विज्ञप्ति दिनांक 14 अगस्त, 2022 को क्रमशः हिन्दी

दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला व हिन्दुस्तान हिन्दी दैनिक आगरा में 15 दिवस में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे किन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये। तत्क्रम में उपविधि का गजट कराये जाने हेतु प्रस्ताव नगर पंचायत बेवर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। जो कि निम्नवत् है—

मेला/हाट/प्रदर्शनी उपविधि/उपनियम

उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा 1916 की धारा 298(1)(त्र)(ङ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत, बेवर, मैनपुरी मेला/हाट/प्रदर्शनी/उपविधि/उपनियम, 2022।

एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्—

उपविधि —

- 1—यह मेला एवं हॉट, प्रदर्शनी उपविधि, 2022 नगर पंचायत बेवर कहलायेगी।
- 2—इस उपविधि के उपबंध नगर पंचायत, बेवर की सीमा में लागू होंगे।
- 3—यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
- 4—नियम या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में—

(क) अधिनियम का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत, बेवर से है।

(ग) प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत, बेवर के प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष से है।

(घ) "मेला अवधि" का तात्पर्य नगर पंचायत, बेवर की सीमा में लगाने वाले समस्त प्रकार के मेला/प्रदर्शनी की अवधि से है।

(ङ) सीमा का तात्पर्य नगर पंचायत, बेवर की सीमा से है तथा भविष्य में सशोधित सीमाये भी इसमें सम्मिलित होंगी।

(च) "फीस" का तात्पर्य मेला अवधि में लगायी गयी फीस की दरों से है।

(छ) "खेल-तमाशों" का तात्पर्य मेला सीमा में लगाये गये खेल तमाशों से है।

(त) "ठेला (रेहड़ी)" का तात्पर्य मेला सीमा में लगाने वाले ठेला (रेहड़ी) से है। जिनकी नाप 6 फीट X 4 फीट है।

(थ) कर्मचारी का तात्पर्य नगर पंचायत, बेवर के कर्मचारी से है जो शुल्क वसूली हेतु अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किये जाते हैं।

(ण) निरीक्षक का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी या ऐसे कर्मचारी से है जिनको नगर पंचायत, बेवर निरीक्षण हेतु अधिकृत करें।

5—नगर पंचायत बेवर मेला शुल्क की वसूली अपने कर्मचारी या ठेकेदार द्वारा करवाने को पूर्ण स्वतंत्र है।

6—समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र मैनपुरी में होगा।

7—कोई वाद-विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

8—मेला अवधि में दो किलोमीटर की दूरी तक कोई व्यक्ति खेल-तमाशा, नौटंकी, झूला, सर्कस, मैजिक शो आदि नगर पंचायत, बेवर की अनुमति लिये बिना नहीं लगा सकेगा।

9—मेला अवधि में नगर पंचायत अपनी भूमि पर निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिये स्वतंत्र होगी।

10—ठेकेदार द्वारा शर्तों के उल्लंघन पर ठेका को निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष का होगा और ठेकेदार द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त मानी जायेगी। पुनः ठेका उठाने का अधिकार नगर पंचायत, बेवर का होगा।

11—कोई भी व्यक्ति नई दुकान, (बक्सा आदि) की मेला सीमा में नहीं खोल सकेगा। यदि पुराने दुकानदार फड़ पर रखकर सामान की बिक्री करता है तो उसे मेला शुल्क देना होगा।

12—मेला में लगने वाले सिनेमा, सर्कस, नौटंकी मैजिक शो, डान्स पार्टी आदि द्वारा आधिकारिक स्वीकृति पार्टियों को जिलाधिकारी / मनोरंजन अधिकारी से स्वंयं लेनी होगी, तभी अपना शो लगा सकेंगी।

13—मेला फीस वसूली कर्ता द्वारा शुल्क दाता को नगर पंचायत द्वारा प्रमाणित रसीद तुरन्त देनी होगी।

14—अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी समस्त मेला सम्बन्धी व्यवस्थाओं का नियमकूल कार्यों का निरीक्षण किसी भी समय पर कर सकेंगे।

15—ठेकेदार को स्वयं अपने खर्च पर रुपया 100.00 प्रति हजार पर वसूली सरकारी दरों से स्टाम्प (अनुबन्ध-पत्र) हेतु जमा करना होगा।

16—मेले के अन्दर सुरक्षा की दृश्टि से लगने वाले शासकीय पुलिस, रेड, कास खोला पाया व नगर पंचायत कैम्प व अग्निशमन कैम्प वसूली से मुक्त रहेंगे। सरकारी विभागों एवं हस्तशिल्प की प्रदर्शनी वसूली से मुक्त रहेगी।

17—विधि विरुद्ध घोषित वाणिज्य संस्था, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक प्रोग्राम आदि नहीं लगाये जायेंगे।

18—मेला लगने वाली समस्त व्यवसायिक संस्थाओं को नगर पंचायत द्वारा क्रमबद्ध व सुन्दरता की दृष्टि से निर्धारित स्थान पर लगाया जायेगा।

19—शुल्क की दरें निम्नलिखित होंगी जो पूर्ण मेला अवधि तक लागू रहेंगी।

क्र०स०	मदों का विवरण	प्रस्तावित दरें पूर्ण मेला अवधि
		रु०
1	सिनेमा, सर्कस, नौटंकी, डांसपार्टी, चिड़ियाघर प्रति प्रोग्राम	20000.00 प्रति प्रोग्राम
2	सोफ्टी प्रति दुकान प्रति प्रोग्राम	45000.00
3	झूला बड़ा	50000.00
4	खजला प्रति दुकान	40000.00
5	झूला छोटे	20000.00
6	मेला फील्ड के अन्दर लगने वाली दुकाने 10 X 10 फुट	1500.00
7	स्थायी ठेला रेहड़ी	50.00 प्रति दुकान
8	अस्थायी ठेला रेहड़ी	50.00 प्रति दुकान
9	चलते फिरते फेरी वाले	20.00 प्रति दुकान
10	चाट की दुकान बड़ी	30000.00
11	झूला बच्चों वाले	30000.00
12	मिट्टी बर्तन की दुकाने प्रति दुकान	1000.00

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके यह आदेश दिया जाता है कि इस नियमावली में दिये गये किसी भी अधिनियम का तथा प्राविधान का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अर्थ दण्ड का भागी रहेगा जिसके जुर्माने की सीमा रु० 3000.00 (तीन हजार) तक हो सकती है। और यदि उल्लंघन करने वाला व्यक्ति उल्लंघन करता रहे तो प्रथम बार के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है जो रु० 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से होगा।

एतदपूर्व यथा उपबंधित के सिवाय यह उपविधि गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से लागू होगी।

ह० (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत बेवर, मैनपुरी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म ओम ट्रेडर्स, 236 जवाहरपुरी जिला बदायूँ उत्तर प्रदेश जिसकी पंजीकरण सं0-B-12418 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 26 नवम्बर, 2010 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म में दिनांक 26 नवम्बर, 2010 को तीन साझेदार श्री प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द्र गुप्ता व रूम सिंह पुत्र श्री गोकिल सिंह एवं राजा राम सिंह पुत्र श्री राम लाल सिंह थे जिन्होंने मिलकर साझेदारी फर्म को प्रारम्भ किया, उपरोक्त फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2012 को संशोधन किया गया जिसमें साझेदार राजा राम सिंह पुत्र श्री राम लाल सिंह स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये व दिनांक 01 जनवरी, 2019 को उनका स्वर्गवास हो गया, तदोपरान्त फर्म में कुल दो साझेदार श्री प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र सुरेश चन्द्र गुप्ता व रूम सिंह पुत्र श्री गोकिल सिंह रह गये यह कि उपरोक्त फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को पुनः संशोधन किया गया जिसमें दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को साझेदार रूम सिंह पुत्र श्री गोकिल सिंह स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये उनकी जगह एक नया साझेदार श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रवि शंकर को फर्म में स्वेच्छा से सम्मिलित किया गया और उसके बाद फर्म में कुल दो साझेदार रह गये 1-प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता व अशोक कुमार पुत्र श्री रवि शंकर रह गये, यह कि उपरोक्त फर्म में दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 को अशोक कुमार पुत्र श्री रवि शंकर गुप्ता स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये व 05 दिसम्बर, 2020 को अशोक कुमार का आकस्मिक निधन हो गया जिसका फर्म द्वारा संशोधन किया गया और फर्म उनकी जगह 01 अप्रैल, 2019 में रिटायर हुए साझेदार रूम सिंह को दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 से सम्मिलित किया गया। अब फर्म में कुल दो साझेदार प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता व रूम सिंह पुत्र श्री गोकिल सिंह रह गये, यह कि उपरोक्त फर्म दिनांक 04 अप्रैल, 2021 को फिर संशोधन किया गया और दो नये साझेदार 1-मंदालसा गुप्ता पुत्री ओम प्रकाश गुप्ता 2-विनय कुमार पुत्र श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता को सम्मिलित किया गया, अब फर्म में कुल चार साझेदार हो गये क्रमशः: 1-प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता 2-रूम सिंह पुत्र श्री गोकिल सिंह 3-मंदालसा गुप्ता पुत्री ओम प्रकाश गुप्ता 4-विनय कुमार पुत्र श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता हो गये। यह कि उपरोक्त फर्म में दिनांक 01 जुलाई, 2021 को पुनः संशोधन किया गया जिसमें दो साझेदार 1-प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता 2-रूम सिंह पुत्र श्री गोकिल सिंह दिनांक 01 जुलाई, 2021 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त (रिटायर) हो गये, अब उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल दो साझेदार क्रमशः: 1-मंदालसा गुप्ता पुत्री श्री ओम प्रकाश गुप्ता निवासी 233, जवाहरपुरी जिला बदायूँ उत्तर प्रदेश 2-विनय कुमार पुत्र श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता निवासी 242, जवाहरपुरी जिला बदायूँ उत्तर प्रदेश के हैं।

मंदालसा गुप्ता,

साझेदार,

ओम ट्रेडर्स, 236 जवाहरपुरी,
जिला—बदायूँ उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिनी के कुछ शैक्षिक अभिलेखों में पिता का नाम बाल कृष्ण पाठक अंकित है जो कि सही है। त्रुटिवश प्रार्थिनी के कुछ शैक्षिक अभिलेखों में पिता का नाम बाल कृष्ण एवं बालकृष्ण पाठक अंकित है। मेरे पिता का सही नाम बाल कृष्ण पाठक है। भविष्य में मेरे पिता को बाल कृष्ण पाठक के नाम से जाना एवं पहचाना जाय।

कविता पाठक पुत्री श्री बाल कृष्ण पाठक,
निवासिनी ग्राम रोहाना, पो० जेठवारा,
तहसील लालगंज, जिला प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे हाईस्कूल सह अंक प्रमाण-पत्र अनुक्रमांक 5093527 में मेरी माता का नाम Anita दर्ज है जो कि गलत है मेरी माता का सही नाम Anita Mishra है। उपरोक्त दोनों नाम मेरी माता का ही है। भविष्य में मेरी माता को उनके सही नाम Anita Mishra पत्नी Pushpraj Mishra के नाम से जाना व पहचाना जाये।

विशाल मिश्रा,
पता—ग्राम व पोस्ट उत्तरी कोटवा,
हनुमानगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम ऋषिका शुक्ला अंकित है और मेरे घर का नाम हिमांशी शुक्ला है। उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे हिमांशी शुक्ला के स्थान पर ऋषिका शुक्ला के नाम से जाना पहचाना एवं पढ़ा जाये। ऋषिका शुक्ला पुत्री श्री सुधीर कुमार शुक्ला पता—३६बी/१४के/१, भावापुर जी०टी०बी० नगर करैली प्रयागराज।

ऋषिका शुक्ला,
पुत्री श्री सुधीर कुमार शुक्ला,
पता—३६बी/१४के/१-भावापुर जी०टी०बी०,
नगर करैली, प्रयागराज।

सूचना

मेसर्स श्री जगदम्बा दाल एंड आयल मिल पता बायपास रोड पुखरायां कानपुर देहात जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि 30 जनवरी, 1991 में रजिस्टर्ड हुई थी जिसमें पार्टनर श्री बालकृष्ण ओमर पुत्र मृतक परागी लाल पता पुखरायां कानपुर देहात एवं श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता पुत्र मृतक छेदी लाल पता पुखरायां कानपुर देहात दो पार्टनर थे। दिनांक 31 जुलाई, 2022 को उक्त फर्म का पुनर्गठन हुआ जिसमें श्री शैलेंद्र कुमार गुप्ता श्री महेंद्र कुमार बिश्नोई एवं गौरव बिश्नोई पुत्र गड़ जगदीश प्रसाद गुप्ता निवासी पुखरायां भागीदार बने एवं श्री बालकृष्ण ओमर पुत्र मृतक परागी लाल निवासी

पुखराया उक्त भागीदारी फर्म से अलग हो गये। अब उनका इस फर्म के लेन-देन व व्यापारिक कार्यों से कोई संबंध नहीं है।

जगदीश प्रसाद गुप्ता,
मेसर्स—श्री जगदम्बा दाल एंड आयल मिल,
बाई पास रोड, पुखरायां,
जिला कानपुर देहात, उ०प्र०।

सूचना

मेसर्स श्री हनुमान सर्विस सेंटर पता बायपास रोड पुखरायां कानपुर देहात है जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि 15 अक्टूबर, 2004 में रजिस्टर्ड हुई थी जिसमें पार्टनर श्री बालकृष्ण ओमर पुत्र मृतक परागी लाल गुप्ता पता ईश्वर चंद नगर पुखरायां कानपुर देहात एवं श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता पुत्र मृतक छेदी लाल गुप्ता पता सुभाष नगर पुखरायां कानपुर देहात दो पार्टनर थे लेकिन 31 जुलाई, 2022 को श्री बालकृष्ण ओमर पुत्र मृतक परागी लाल पता ईश्वर चंद नगर पुखरायां, कानपुर देहात जो फर्म से अलग हो गए हैं और उनके स्थान पर तीन नये पार्टनर आ गये हैं जिनका नाम श्री शैलेंद्र कुमार गुप्ता श्री महेंद्र कुमार बिश्नोई एवं गौरव बिश्नोई पुत्र गड़ जगदीश प्रसाद गुप्ता पता सुभाष नगर का पुखरायां कानपुर देहात है।

जगदीश प्रसाद गुप्ता,
मेसर्स—श्री हनुमान सर्विस सेंटर,
कार्यालय—प्लाट न० १४२,
बाई पास रोड, पुखरायां,
जिला कानपुर देहात, उ०प्र०।

सूचना

सूचित किया जाता है कि वासन्स एंड वासन्स कम्पनी का पता मानवता निवास बरिया घाट वासलीगंज मिर्जापुर से बदल कर कृष्ण चमन लोहिया तालाब मिर्जापुर हो गया है, कम्पनी के दो पार्टनर चन्द्रमोहन वासन व रवि कुमार वासन देख रहे हैं। तीसरे पार्टनर कृष्णावन्ती वासन की मृत्यु हो चुकी है। रवि कुमार वासन पुत्र चमन लाल वासन निवासी म०न० १५२८/६वार्ड न० ९ घुरहू पट्टी, सिविल लाईन्स, जिला मिर्जापुर।

रवि कुमार वासन।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का घर का नाम प्रांशु मौर्य है शैक्षिक अभिलेखों में मेरे पुत्र का नाम आर्यन मौर्य पुत्र कृष्ण चन्द्र मौर्य अंकित है। त्रुटिवश टाटा ए०आई०जी लाइफ इन्श्योरेन्स में घर का नाम प्रांशु मौर्य अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे पुत्र का ही है। भविष्य में मेरे पुत्र का नाम आर्यन मौर्य पुत्र कृष्ण चन्द्र मौर्य के नाम से जाना व पहचाना जाये।

कृष्ण चन्द्र मौर्य,
निवासी कपुरी गोदाम चौराहा,
नूरपुर, पो० नसरत पुर,
थाना साराव, जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे घर का नाम गुरुजीवन सिंह पुत्र स्व० संजीव सिंह है जबकि मेरे शैक्षिक अभिलेखों आधार कार्ड, पैनकार्ड, में मेरा नाम गुरशीत सिंह पुत्र स्व० संजीव सिंह है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। त्रुटिवश एल०आई०सी० की पालिसी सं० 231212790 में मेरा घर का नाम अंकित हो गया है। भविष्य में गुरुशीत सिंह पुत्र स्व० संजीव सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

गुरशीत सिंह,
डी-१/८०१ एल्डिको गार्डन,
थाना-रायपुरवा, कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का नाम मोहित गुप्ता पुत्र श्री सुनील कुमार गुप्ता है मेरे शैक्षिक अभिलेखों आधार कार्ड, पैन कार्ड, में असित गुप्ता पुत्र श्री सुनील कुमार गुप्ता अंकित है त्रुटिवश एल०आई०सी० पालिसी सं० 231211562 में मेरा घर का नाम मोहित गुप्ता अंकित हो गया है उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं भविष्य में मुझे असित गुप्ता पुत्र सुनील कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

असित गुप्ता पुत्र श्री सुनील कुमार गुप्ता,
निं० जे० ब्लाक, 609,
विश्वबैंक बर्रा, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम LAXMI NARAYAN (लक्ष्मी नारायण) पुत्र चन्द्र दत्त है। त्रुटिवश सेवा पुस्तिका/PPO में मेरा नाम LAXAMI NARAYAN अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम LAXMI NARAYAN (लक्ष्मी नारायण) पुत्र चन्द्र दत्त के नाम से जाना और पहचाना जाये।

लक्ष्मी नारायण,
पुत्र चन्द्र दत्त,
निवासी-विद्यानगर, निलमधा,
लखनऊ, उ०प्र०-२२६००२

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म सर्वश्री जनरल इन्जीनियरिंग वर्कर्स सी० ३५ एवं सी० ३६ यू०पी०एस०आई०डी०सी० इन्डस्ट्रियल एरिया, नैनी प्रयागराज-२११०१० में दिनांक ३१ मार्च, २०२१ तक दो साझेदार, प्रथम श्री अशोक मित्तल पुत्र श्री द्वारका दास निवासी ५, लूकरगंज, प्रयागराज एवं द्वितीय श्री अनिल कुमार सेठ पुत्र श्री राम कृष्ण सेठ निवासी १३२A/१

पी०एस०यू०पी०-३६ हिन्दी गजट-भाग ८-२०२२ ई०।
मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ०प्र०, प्रयागराज।

अलोपीबाग, प्रयागराज थे। परन्तु दिनांक ०१ अप्रैल, २०२१ से उक्त दोनों साझेदारों के अतिरिक्त दो और साझेदार श्री आभासमित्तल पुत्र श्री अशोक मित्तल निवासी ५, लूकरगंज, प्रयागराज एवं श्री मयंक सेठ पुत्र श्री अनिल कुमार सेठ निवासी १३२A/१ अलोपीबाग, प्रयागराज सम्मिलित हो गये हैं। इस प्रकार कुल चार साझेदार उक्त फर्म में हैं।

अशोक मित्तल।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स मार्लती प्लाटो इण्डस्ट्रीज, हेड आफिस ४०६ जे०ड, वेस्ट बशारतपुर हरिहरपुरम, जनपद-गोरखपुर में साझेदार डीड दिनांक ०१ अप्रैल, २०२२ को सहायक निबन्धक, फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स जनपद-गोरखपुर के चार पार्टनर क्रमशः १-श्री प्रतीक चाचान पुत्र श्री अनिल कुमार चाचान, निवासी श्री श्याम कुंज, ४०६ जे०ड, वेस्ट, बशारतपुर, जनपद- गोरखपुर, २-श्रीमती तनुश्री चाचान पत्नी श्री प्रतीक चाचान, श्री श्याम कुंज, ४०६ जे०ड, वेस्ट, बशारतपुर, जनपद गोरखपुर ३-श्री अनिल कुमार चाचान पुत्र श्री के०सी० चाचान निवासी श्री श्याम कुंज, ४०६ जे०ड, वेस्ट, बशारतपुर, जनपद गोरखपुर, ४-श्रीमती साधना चाचान पत्नी श्री अनिल कुमार चाचान, निवासी श्री श्याम कुंज, ४०६ जे०ड, वेस्ट, बशारतपुर, जनपद गोरखपुर, २-श्रीमती साधना चाचान पत्नी श्री अनिल कुमार चाचान निवासी श्री श्याम कुंज, ४०६ जे०ड, बशारतपुर, वेस्ट, जनपद गोरखपुर, दिनांक ०१ अप्रैल, २०२२ से अलग हो रहे हैं। तथा फर्म श्रीमती तनुश्री चाचान पत्नी श्री प्रतीक चाचान श्री श्याम कुंज, ४०६ जे०ड, वेस्ट, बशारतपुर, जनपद गोरखपुर वर्तमान साझेदार के रूप में पुजीकृत हैं। अब फर्म में वर्तमान दो साझेदार मौजूद हैं। फर्म का पूर्व व्यवसाय का पता आफिस न०-३, ५ वां तल, गैलेन्ट लैण्डमार्क, बैंक रोड, जनपद गोरखपुर था जिसे परिवर्तित कर वर्तमान में हेड आफिस ४०६ जे०ड, वेस्ट बशारतपुर हरिहरपुरम, जनपद गोरखपुर हो गया है।

प्रतीक चाचान,
साझेदार।